मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 32 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 6 – 12 अगस्त 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

नाकाम डबल इंजन सरकार, मणिपुर में हाहाकार.....5

एक घुमक्कड़ क्रांतिकारी की जीवनगाथा.....8–9

'प्रेमचंद का साहित्य और किसानों के सवाल'.....11

इंडिया का विचार

डी. राजा

सात दशक से अधिक समय पहले डॉ. अम्बेडकर ने सतर्क किया था कि ''26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोध के एक जीवन में प्रवेश करने जा रहे है। राजनीति में हमारे पास समानता और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता होगी''।

हमारे समय में भी हम लगातार इन अंतर्विरोधों का सामना कर रहे हैं परंतु एक अत्यधिक गंभीरतर स्तर पर। आज समानता की अवधारणा मात्र ही, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर समानता हमले का शिकार है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार की एक सबसे बड़ी खराबी यह है कि वह आरएसएस के इशारे पर एक असमान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। इसके कारण देश को भारी नुकसान हो रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में असमानता दिखाई पड़ती है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव में, जाति के संबंध में लगातार बढ़ रही कठोरता में, बढ़ता नारी द्वेष में और चंद लोगों के हाथ में धन–दौलत के संकेन्द्रण में–हर कहीं असमानता लगातार बढ़ रही है।

इसका समाधान बढ़ती असमानता की जड़ पर और आरएसएस–भाजपा के एकाश्मक सांप्रदायिक क्रोनीवाद पर प्रहार करने के लिए धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतों की एकता में है। हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकहितकारी तानेबाने पर हो रहे हमले का प्रतिरोध करने और उसे नाकाम करने के लिए इतिहास का तकाजा है कि भारत को बचाने के लिए और भारत को बदलने के लिए धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतें एकताबद्ध हों।

नवगठित ''भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन'' (इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लूजिव अलायन्स–आईएनडीए–इंडिया) का गठन जबर्दस्त विचार–विमर्श और बहस का विषय बन गया है। एक तरफ, ''इंडिया'' के प्रादुर्भाव ने हमारी जनता के धर्मनिरपेक्ष– लोकतांत्रिक–प्रगतिशील तबकों को आरएसएस–भाजपा के घृणास्पद, फूटपरस्त एवं क्रोनी पूंजीवादी शासन का एक सक्षम एवं व्यवहार्य विकल्प प्रदान किया है।

दूसरी तरफ, धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतों की एकता को मजबूत होते हुए देखकर दक्षिणपंथी आरएसएस नियंत्रित इकोसिस्टम में घबराहट पैदा हो रही है और एकता की जो ताकतें हमारे धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक गणतंत्र के विचार की रक्षा के लिए एकताबद्ध हुई हैं उसने उनकी एकता के संबंध में अनर्गल बातें कहना शुरू कर दिया है। मोदी ने नवगठित गठबंधन ''इंडिया'' की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर इस अनर्गल प्रलाप के अभियान को शुरू किया है। उन्होंने जानते–बूझते हुए इस इतिहास को भुला दिया कि देशभक्त एवं वामपंथी ताकतों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदाईश ब्रिटिश राज को भारत से उखाड़ फेंका था। उन्हें यह भूलना जरूरी भी था क्योंकि वह जानते हैं और हर कोई जानता है कि जिस समय देश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा था वह कौन सी ताकतें थी जो वफादारी के साथ अंग्रेज सरकार की खिदमत कर रही थी।

भाजपा के सत्ता में आने के बाद देश में हर कहीं अभूतपूर्व कुशासन का आलम है। नोटबंदी– जिसके कारण देश में पूरी तरह अफरा–तफरी के हालात बन गए थे जैसे तानाशाही सनक भरे कदमों के कारण अर्थव्यवस्था का एक के बाद दूसरा क्षेत्र कठिनाइयों का शिकार होता चला जा रहा है। जल्दबाजी में लाये गए संघात्मकता विरोधी जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ। कोविड के संकट के गलत हैंडलिंग के कारण वह एक तबाही भरा संकट बन गया। मोदी सरकार के दौरान असमानता बढ़ी है क्योंकि कारपोरेट तबके को एक के बाद दूसरा फायदा पहुंचाया जा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था के अति–आवश्यक क्षेत्र–सार्वजनिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

भाजपा–आरएसएस सरकार के कार्यकाल में सामाजिक और विकास संबंधी सूचकांकों में भारत की लगातार गिरावट एक आम बात बन गई है जिससे हमारे समाज के सबसे कमजोर तबकों की स्थिति के बदतर होने का पता चलता है। यह कोई संयोग मात्र नहीं है कि पिछले नौ सालों में सबसे अमीर लोगों के धन–दौलत में कई गुना वृद्धि हुई है; यह सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से हुआ। क्रोनी पूंजीवाद का भाजपा मॉडल गरीबों से सब कुछ छीनता है और कारपोरेटों पर फायदों की बरसात करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है; समाज के तमाम तबकों के लोग विरोध में सड़कों पर उतरे हैं।

मोदी सरकार के दौरान हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का भारी क्षरण हुआ है। भाजपा की सत्ता की भूख ने समाज के टुकड़े–टुकड़े कर दिए हैं; देश की जनता के बीच फूट के गहरे बीज बो दिए हैं। धर्म एवं जाति, भाषा एवं क्षेत्र के आधार पर जनता को बांट कर आरएसएस –भाजपा हमारे देश के विकास को अवरूद्ध कर रहे हैं। उन्होंने अपने अंग्रेज आकाओं से ''फूट डालो और राज करो'' के फूटपरस्ती के खेल को सीखा है और उसी तरीके को इस्तेमाल कर देश पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं।

उनके इस तरह के घटिया तौर–तरीकों के विनाशकारी नतीजे समूचे देश में दिखाई पड़ रहे हैं। इसका सबसे हाल का उदाहरण मणिपुर राज्य है; यह समूचा राज्य लंबे अरसे से जल रहा है, अशांति का शिकार है और अन्यथा अत्यंत मुखर प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। सरकार की आलोचना की आवाजों को नृशंस दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल कर जबरन खामोश किया जा रहा है। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और हमारे संविधान ने जिन मूल्यों एवं मानदंडों को लोगों के दिलों में भरा था उनमें आम गिरावट आ गई है। हमारे देश में लोकतंत्र का अस्तित्व बना रहे यह आज हमारे सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है। नवगठित गठबंधन ''इंडिया'' के संबंध में जो बहस चल रही है उसे इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

हमारे संवैधानिक मूल्यों के निर्ममतापूर्वक कुचले जाने का विरोध करने और जो विचार हमारी जनता को जोड़कर रखता है उसकी मर्यादा बनाए रखने के लिए लंबे समय से ऐसे गठबंधन की जरूरत महसूस की जा रही थी। विशेष तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राय थी कि भाजपा का केंद्र की सत्ता में आना सरकार का परिवर्तन मात्र नहीं था बल्कि एक ऐसा गुणात्मक परिवर्तन था जिससे देश के संवैधानिक तानबाने को नुकसान पहुंचेगा। हमने भाजपा का राजनीतिक एवं वैचारिक तौर पर सामना करने के लिए धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक देशभक्त ताकतों की एकता पर जोर दिया था।

हिन्दुत्व क्रोनीवाद का विकल्प राजनीतिक स्पेक्ट्रम के वामपंथ द्वारा पेश किया जा सकता है और आरएसएस–भाजपा से आमूलचूल भिन्न एकताबद्ध ब्लॉक का एजेंडा देश को आगे ले जा सकता है। अतीत में भी जब एकताबद्ध धर्मनिरपेक्ष ताकतों का एक दुर्जेय गठबंधन बनाया गया तो भाजपा और उसके सहयोगियों को बहुमत हासिल करना मुश्किल हो गया था।

धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतों की एकता न केवल वोटों के बंटवारे को रोकती है बल्कि इस प्रकार का एक गठबंधन एक वैकल्पिक एजेंडा पेश कर, जनता के सभी तबकों की आवाज बनकर भाजपा के बहुसंख्यकवादी एजेंडे की काट कर सकता है। यह बात रेखांकित की जानी चाहिए कि इस तरह के ब्लॉक के घटकों को आपस में बेहतर समझ पैदा करने के लिए और परस्पर विश्वास को बढ़ाने के लिए एक–दूसरे को एकोमोडेट करना चाहिए। भाजपा को हराने और देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत साझा संकल्प उभर कर सामने आया है। गठबंधन की बारीकियों और विवरणों को राज्य स्तर पर तय किए जाने की जरूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नवगठित गठबंधन ''इंडिया'' का सबसे बड़ा घटक है; उसका पूरे देश में संगठन है; अतः इस संबंध में उसकी खास जिम्मेदारी है।

इस गठबंधन के निर्माण के लिए जून में पटना में एक मीटिंग हुई थी जिसमें 15 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था। वहां सहमति बनी थी कि भाजपा को हराकर संविधान, और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की मर्यादा बनाए रखने के लिए विपक्षी पार्टियों को एक छतरी के अंतर्गत लाया जाए। इससे आगे बढ़ते हुए बंगलुरू में एक मीटिंग हुई जिसमें 26 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस एकताबद्ध ब्लॉक का नाम ''भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन'' (इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लूजिव अलायन्स–आईएनडीए) अर्थात ''इंडिया'' रखने का फैसला किया गया।

विपक्ष की एकता की इस कोशिश से भाजपा सरकार को चिंता हो उठी। यह इस बात से जाहिर होता है कि जिस दिन ''इंडिया'' में शामिल पार्टियों की बंगलुरू में मीटिंग हुई उसी दिन भाजपा ने निष्क्रिय पड़े एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स) की मीटिंग बुलाई। जो पार्टी ताल ठोक कर कह रही थी ''एक अकेला सब पर भारी'' उसे धर्मनिरपेक्ष–लोकतांत्रिक ताकतों की बढ़ती एकता के कारण कम से कम 37 पार्टियों को अपने साथ लेना पड़ा। स्वयं इस बात से एकता के जबर्दस्त महत्व और इस एकता ने

शेष पेज 6 पर...

विकास को चुनौती

संपादकीय

निजीकरण की अपनी नीति के साथ बीजेपी–संघ की सरकार आक्रामक रूप से आगे बढ़ती जा रही है। अपनी एक मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में, बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा कि ''हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र का जन्म ही होता है मरने के लिये।'' ये शब्द हमारे संविधान और संसद की मान्यताओं के बिल्कुल ही विरूद्ध है। हमारा समाज प्रतिबद्ध है एक ऐसे समाज को बनाने के लिये जिसकी बुनियाद समाजवाद के सिद्धांतों पर टिकी है। इस व्यवस्था के लिये अनिवार्य है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की निर्णायक ऊंचाईयां और उसकी रणनीतियां साथ हों। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की लंबे अरसे तक चलने वाली गुलामी में बुनियादी ढांचे का ध्वस्त होना भी अनिवार्य है और उसका पुनर्निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। इसका अर्थ ही है कि हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिये प्रत्येक अवसर सुलभ होगा और अब कोई अधिनायकतंत्र भी संभव नहीं होगा जहां एक ही व्यक्ति के हाथों में ही सब कुछ हो। यह तभी संभव हो सकता है जब जनवाद के साथ सामाजिक न्याय भी होगा। इन कोशिशों के लिये धन की आवश्यकता होगी। और इसके लिये राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता होगी। इसमें पहला कदम जीवन बीमा की ओर था और उसके साथ ही इंपीरियल बैंक की ओर। जल्द ही राष्ट्रीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास की शुरुआत हुई और अन्य प्रमुख बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। उत्पादन के क्षेत्र में एक उपयुक्त और विशाल व्यवस्था तैय्यार होती गई जनता के पैसों को समुचित रूप से लगाने के लिये कदम उठाए गए और सिर्फ अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही उत्पादन नहीं हो रहा था, बल्कि उसके निर्यात की भी कोशिश हो रही थी।

यह 1969 का साल था, जब सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का क्षण आया। चौदह बड़े कमर्शियल बैंकों का जो इजारेदार घरानों के हाथों में थे, राष्ट्रीयकरण हो गया। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रीयकरण के बावजूद निजी क्षेत्र के उद्योगों और व्यापार की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जायगा। राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई थी उत्पादन के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये। इसमें विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में, लघु उद्योगों में और उनके लिये भी जो अपना उद्योग चला रहे थे, ध्यान दिया जाता था। राष्ट्रीयकृत बैंक नए और बढ़ते हुए औद्योगिक विकास के कदमों को भी सशक्त बनाने में लगे हुए थे और साथ ही पिछड़े और उपेक्षित इलाकों का भी उद्धार कर रहे थे। सार्वजनिक स्वामित्व द्वारा स्पेकुलेटिव और अनुत्पादक क्षेत्रों में व्यर्थ के व्यय को भी रोकने की चेष्टा लगी हुई थी। उद्देश्य था थोड़े से हाथों में नियंत्रण को सिमटने से रोकना, कर्ज का मिलना आसान करना, खासकर अत्यावश्यक क्षेत्रों में कर्ज का पहुंचना और बैंक की व्यवस्था में अधिक निपुणता लाने की कोशिश, उत्पादक और व्यवसायियों की नयी श्रेणियों को प्रेरित करना और इस सबके लिये जरूरी था पूंजी और जनता की कुशलता का समन्वय।

यह समाज के आगे बढ़ते कदमों के लिये सहायता देने के लिये किया गया। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा कि राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था जनता की बचत की रकम को इकट्ठी कर उसे कृषि क्षेत्र में निवेश किया जाए, साथ ही उन क्षेत्रों को भी साथ में लिया जाय जो जरुरतमंद हों। उद्देश्य था सबको साथ लिया जाए, और उनके हुनर और पूंजी के साथ बढ़ते जाना हो। इन विकास परियोजनाओं का उद्देश्य था उन्नति की उच्चतर दर, और साथ ही गरीबी की निम्नतर होती दर।

इस स्थिति में असंख्य शाखाएं खुलीं। जमा होने वाली रकम में भी बढ़ोतरी होने लगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सिर्फ दो सालों में, बैंकों का ऋण, जो प्राथमिकता के निवेशों में लगता था, वह चौदह प्रतिशत से इकतालीस प्रतिशत हो गया। गैर–बराबरी को ख़त्म करने की ओर भी अभूतपूर्व सफलता मिल चुकी थी। बैंक नीति इस कोशिश में थी कि आय की असमानता में लगातार कमी आए इन सारी नीतियों के चलते न सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंकों का बचाव हुआ, बल्कि यहां की पूरी अर्थव्यवस्था पर 2007–08 में चल रहे मेल्ट डाउन का आक्रमण भी नहीं हो पाया।

इन सारी सफलताओं के बावजूद चुनौतियां चौखट पर टिकी रहीं। बचत की निधियों में वृद्धि होती रही, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था वित्त पूंजी में बदलती रही, जिसे उसकी बढ़ती परिपक्वता माना गया। व्यवस्था से कॉरपोरेट क्षेत्र भी लाभ उठाता रहा। आम जनता के कल्याण की कामना क्रमशः फीकी पड़ती रही, यह सरकार का कर्तव्य नहीं रह गया। अलग–अलग पार्टियों की सत्ताएं देश में राज करती रहीं, जिनमें भाजपा भी शामिल हुई, शताब्दी की शुरुआत में। लेकिन यह 2014 में ही हुआ कि बीजेपी–संघ के हाथों में सत्ता आई और निजीकरण की वृहत् स्तर पर शुरुआत हुई। केंद्र में सरकार ने निजीकरण से 4.04 लाख करोड़ का फायदा उठाया जिनमें शामिल थे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जो प्राथमिकता में उच्चतम स्थान रखते थे। ऐसी दस कंपनियों के साथ, जिनमें एयर इंडिया भी है, सरकारी ख़जाने को 69,412 करोड़ का लाभ पिछले आठ सालों में हुआ। शेयरों की वापसी खरीद में पैंतालीस उद्योगों के शेयर से 45.104 करोड़ का लाभ हुआ। राष्ट्रीकृत उद्योगों का निजीकरण चलता रहा।

जब प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक उद्योगों की मृत्यु की चर्चा की तो इसमें देश के जनवाद के ध्वस्त होने की भी ख़नक थी। राष्ट्रीयकरण देश की रीढ़ है, और यह देश के विकास में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसका अंतिम उद्देश्य ही है पूरी उत्पादन व्यवस्था का समाजीकरण। इस सामाजिक–आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिये, राष्ट्रीयकरण के क्रम में देश की आर्थिक स्थिति की सुरक्षा प्राथमिक है। यह क्षेत्र सरकार के अधिकार में है। सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा जनहित में बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिये भी कदम उठाने की कोशिश की जाती है। जब राष्ट्रीयकरण की शुरुआत हुई, तो बेरोजगारी दूर करने की ओर भी कदम उठाए गये। रोजगार के अवसर बनाने की भी कोशिश होती रही। जनतंत्र को सशक्त बनाने के लिये राष्ट्रीय ईकाईयों द्वारा कदम उठाए गए।

सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ, हमारी गंगा–जमुनी संस्कृति, हमारा संविधान और जनतांत्रिक विचारधारा को बचाए रखने की सारी कोशिशें आज भयंकर चुनौती का सामना कर रही है। इसका ज्वलंत उदाहरण है मणिपुर, जहां इंसानियत ही लपटों में जल रही है। भारत में ऐसी बर्बरता कभी देखी नहीं गई। यह सिर्फ दो कबीलों का वैमनस्य नहीं है, न ही इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई निर्देश किसी कबीले की हैसियत बदलने से जुड़ा होने का कारण बना है। यह तो वह फूटती हुई ज्वालामुखी है जो ज़िन्दगी की बुनियादी जरुरतों के पूरा नहीं होने, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंत में साधनों की घोर कमी, और इन सबकी सरकार द्वारा लंबे समय से उपेक्षा ही है, विस्फोरण स्थिति आज हमारे सामने हैं। कोशिशें इसके लिये भी चल रही हैं कि असंतोष की यह तीव्रता बनी रहे।

हरियाणा भाकपा ने राज्य में हिंसा पर जताई चिंता

पानीपत, 1 अगस्त 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी ने नूंह जिले में उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति पर गहरी चिंता प्रकट की है और इसके लिए सरकार तथा प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। यहां जारी एक प्रैस बयान में भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा सरकार अस्तित्व में आई है तब से मेवात को सांप्रदायिक ढंग से निशाने पर लिया जाता रहा है। फिलहाल जो घटित हुआ है वह सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आरएसएस से संबंधित विश्व हिंदू परिषद,बजरंग दल आदि की ओर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान था जिसमें गत दिनों जुनैद और नासिर को जिंदा जलाकर मारने के प्रमुख आरोपी मोनू मानेसर ने खुद वीडियो जारी करके अपनी टीम के साथ भाग लेने की घोषणा के साथ बड़ी संख्या में सांप्रदायिक लामबंदी का आह्वान किया था। कश्यप ने कहा कि जानकारी मिली

है कि स्थानीय जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन से मिल कर चेताया था और इस यात्रा के निकलने से शांति भंग होने की आशंका प्रकट की थी। परन्तु प्रशासन की तरफ से न सिर्फ इस यात्रा को निकालने की अनुमति दी गई बल्कि अन्य एहेतियादी कदम भी नहीं उठाए। नतीजतन वही हुआ जिसकी आशंका स्थानीय लोगों ने प्रकट की थी। जानकारी मिली है कि बङे पैमाने पर आसपास के राज्यों और जिलों से साम्प्रदायिक लामबंदी की गई और गाङियों के काफिले के साथ यात्रा निकालते हुए भङकाऊ नारे लगाए गए। विश्व हिन्दू परिषद के सुरेन्द्र जैन के साथ खुद मोनू मानेसर भी इस यात्रा में शामिल बताया गया है।

रिपोर्ट है कि हवाई फायरिंग, पत्थरबाजी, तोङफोङ और आगजनी की वारदातें हुई हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी है। सम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में मदद करने के बजाए कुछ शरारती तत्व पलवल, सोहना तक एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पार्टी ने राज्य के मुख्यमंत्री से तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तमाम नागरिकों से अपील की है कि आपसी सद्भाव बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें और साम्प्रदायिक तथा असामाजिक तत्वों को और ज्यादा माहौल बिगाड़ने का मौका न दें।

इसके अलावा भाकपा राज्य सचिव ने मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि नूंह में एक सांप्रदायिक संगठन की ओर से निकाली गई कथित ब्रजमंडल यात्रा के दौरान जो हिंसक घटनाएं घटी हैं वह सबके लिए बेहद चिंताजनक है। स्वतंत्र सूत्र बताते हैं कि इस यात्रा को लेकर नूंह के जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन को पहले ही खबरदार किया था कि इससे शांति भंग होने की गंभीर आशंका है। फरवरी 2023 में जिस प्रकार राजस्थान के घाटमीका गांव के दो युवकों जुनैद व नासिर की जलाकर मारने की जघन्य वारदात की गई थी उसके मद्देनजर ऐसी आशंकाएं निराधार नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि प्रशासन ने सांप्रदायिक संगठनों द्वारा ऐसी यात्रा को न केवल अनुमति दी बल्कि आशंका के बावजूद किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के पर्याप्त प्रबंध भी नहीं किये। ऐसा क्यों हुआ है यह वास्तव में प्रशासन की मंशा पर ही सवाल खड़े करता है। आपकी सरकार को इसकी पूर्व सूचना नहीं रही होगी ऐसा नहीं लगता।

बहरहाल, अब स्थिति बेहद तनावपूर्ण बताई जा रही है। इसलिए उपरोक्त सवालों और हिंसा की जिम्मेदारी तो निष्पक्ष जांच से ही हो पाएगी। फिलहाल तो प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तुरंत प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस पक्ष पर कोई भी कोताही असामाजिक तत्वों को परस्पर सद्भाव को बिगाड़ने का मौका प्रदान करेगी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी आपसे पुरजोर आग्रह करती है कि आप स्वयं इस मामले को प्राथमिकता पर लेकर कारगर हस्तक्षेप करें।

भाजपा भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ सम्मेलन संपन्न

झारखण्ड की राजधानी में संयुक्त किसान मोर्चा की महारैली

महेन्द्र पाठक

हजारीबागः संयुक्त किसान मोर्चा का राज्य सम्मेलन आकाशदीप होटल नवाबगंज हजारीबाग में 4 सदस्यीय अध्यक्षमंडल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। किसान संग्राम समिति के राजेंद्र गोप, अखिल भारतीय किसान सभा के गणेश महतो, अखिल भारतीय किसान महासभा के बी एन सिंह, झारखंड राज्य सभा के सुफल महतो ने संयुक्त रूप से इसे संचालित किया।

संयुक्त किसान मोर्चा के सम्मेलन का उद्घाटन अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी अतुल कुमार अनजान ने किया। सम्मेलन का आधार पत्र अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक महेंद्र पाठक ने रखा। सम्मेलन में मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अनजान। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक महेंद्र पाठक, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, पूर्व विधायक कृष्णा प्रसाद, विधायक सुदामा प्रसाद, पूर्व विधायक आनंद महतो, पूर्व विधायक गौतम सागर राणा, केडी सिंह, किसान नेता विमल दास, झारखंड राज किसान सभा के सुफल महतो, सुजीत सिन्हा, भीम आर्मी सेना के चंदन कुमार सहित कई साथियों ने भाग लिया।

अतुल कुमार अनजान ने कहा कि जात पात के आधार पर मोदी सरकार देश के लोगों को बांट रही है। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र हो रही हैं। मणिपुर जल रहा है और एक साजिश के तहत पूरे देश में 2024 के चुनाव को देखते हुए अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जात और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। खेती का जिम्मा कारपोरेट के हाथ दिया जा रहा है। किसानों आत्महत्या कर रहे हैं, मोदी सरकार चुप है, किसानों के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी मोदी की सरकार कर रही है। धरती के नीचे से लेकर आसमान के ऊपर तक सब कुछ अडानी के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में 2024 के आम चुनाव में एनडीए एवं इंडिया में सीधी लड़ाई होगी। देश कि जनता के कुशासन का जबाब वोट के माध्यम से देकर भाजपाइयों को सता से बेदखल करेगी। हजारीबाग की जनता से अपील करते हुए अनजान ने कहा कि हजारीबाग की जनता एक बार फिर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता को संसद के अंदर देखना चाहती है। खचाखच भरे सभागार में लोगों के मनोबल को बढ़ाते हुए कहा कि हजारीबाग से भाकपा ही भाजपा को दो बार हरा चुकी है। इस बार भी भाजपाई हारेंगे।

पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि अदानी कोल ब्लॉक बड़कागांव में दिया गया वहां पर किसानों को पुलिसिया दमन का शिकार होना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोग एकजुट हैं। सरकार कोल ब्लॉक को अविलंब रद्द करे। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा जन आंदोलन को कुचलने नहीं दिया जाएगा। और झारखंड में किसानों पर दमन होता है, जोगी और हेमंत को कौन से फर्क पड़ता

है। इसीलिए जन आंदोलन को विकसित करने के लिए जन आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। विधायक सुदामा प्रसाद ने राष्ट्रीय एवं राज्य की राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि देश कंगाली की ओर जा रहा है। किसान हाशिए पर जा रहे हैं। आने वाले 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए सब को एकजुट होना पड़ेगा। सम्मेलन में पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। सम्मेलन को कई लोगों ने संबोधित किया और कई प्रस्ताव पास किए, सम्मेलन में मुख्य रूप से 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सभी संगठनों से अध्यक्ष सचिव को पदाधिकारी बनाया गया। महेंद्र पाठक, सुजीत कुमार, के डी सिंह, कृष्ण कुमार मेहता, सुफल महतो, राजेंद्र गोप, शाहिद अंसारी, रमेश कुमार सिटी, निजाम अंसारी, यादव प्रदीप कुमार, अनवर हुसैन, निजाम अंसारी, कृष्णा मेहता, चंदन कुमार, अर्जुन यादव, इंद्रमणि देवी, चांद खान धर्मवीर सिंह, विमल दास, असीम सरकार सहित कई लोगों ने सम्मेलन को संबोधित किया।

सम्मेलन में भविष्य के नियत कार्य तय किये गयेः

1. झारखंड के सभी जिलों, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन किया जाए।

2. हर स्तर पर संयुक्त आंदोलन विकसित किया जाए।

3. गरीब लघु एवं सीमांत किसानों को आंदोलन से जुड़ने के लिए उनकी व्यापक मांगों को जोड़ा जाए।

4. घर–घर जाकर लोगों के किसान विरोधी सरकार की नीतियों की जानकारी दिया जाए।

5. लोकल मुद्दों को जोड़कर आंदोलन तेज किया जाए।

6. प्रमंडलीय एवं जिला के प्रखंड स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा कन्वेंशन आयोजित की जाए।

7. सभी जिलों में बड़ी–बड़ी किसान पंचायत लगायी जाए।

8. राज्य स्तरीय किसान रथ यात्रा निकाली जाए एवं 26 नवंबर 2023 को रांची में किसान संगठनों की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महारैली की आयोजन किया जाए।

इसके अलावा संयुक्त किसान सम्मेलन ने अपना एक मांगपत्र भी तैयार कियाः

1. झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करो और बड़े पैमाने पर राहत कार्य चालू करो।

2. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू किया जाए।

3. गैरमजरूआ जमीन के भूमि बैंक को रद्द किया जाए।

4. गैरमजरूआ जमीन की बंद पड़े रसीद को अविलंब चालू किया जाए।

5. राष्ट्रहित और राज्य हित में गैरमजरूआ जमीन के अधिग्रहण पर रैयती की तरह मुआवजा दिया जाए।

6. वनाअधिकार कानून 2006 लागू किया जाए एवं वन अधिकार कानून संशोधन बिल रद किया जाए।

7. बरसों से जंगल के जमीन पर खेती करने वाले लोगों को बन पट्टा दिया जाए।

8. खनिज संपदा वाली जमीन के अधिग्रहण पर 25 प्रतिशत मुनाफा किसानों को दिया जाए।

9. बहू फसली जमीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई जाए।

10. राष्ट्र एवं राज्य हित में अधिग्रहण की गई जमीन के बदले कानून बनाकर दूसरे जगह पर जमीन उपलब्ध कराया जाए। यानी जमीन के बदले जमीन देने कि योजना बनाकर जमीन दिया जाये।

11. 9 अगस्त 2023 को कारपोरेट भारत छोड़ो के नारों के साथ सभी प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन आयोजित किये जाए।

12. सितंबर–अक्टूबर महीने में सभी जिलों में छोटी बड़ी नुक्कड़ सभा, जीप, जत्था,मोटरसाइकिल जत्था, पैदल जत्थे के माध्यम से भाजपा भगाओ, खेती बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, के नारे के साथ बड़ा जन जागरण अभियान चलाया जाए।

13. 26 नवंबर 2023 को सभी जन संगठनों को लेकर रांची में एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जाए।

भाकपा ने यात्रियों की हत्या, हरियाणा दंगों की निंदा की

नई दिल्लीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 2 अगस्त 2023 को निम्नलिखित बयान जारी कियाः

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल हाल ही में जयपुर–मुंबई ट्रेन में यात्रियों की हत्या की निंदा करता है, जिसे हमलावर का मानसिक पतन करार दिया जा रहा है। यह तथ्य का अत्यधिक सरलीकरण है और इसका उद्देश्य वास्तविक तस्वीर से ध्यान हटाना है। हरियाणा में हुए दंगों और आगजनी में पांच से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें इमाम और दो होम गार्ड भी शामिल हैं। पिछले पांच महीनों से कुख्यात हत्यारे मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने में पुलिस की विफलता और ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा में भाग लेने की उसकी घोषणा ने नूंह (हरियाणा) में स्थिति को भड़का दिया, जो एक अति संवेदनशील सांप्रदायिक स्थान है। इसके अलावा जिला खुफिया प्रमुख द्वारा मुस्लिम इलाकों से जुलूस की अनुमति देने पर सांप्रदायिक झड़प भड़कने की चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद झड़पें हुई। सांप्रदायिक तनाव, जो सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा अपनाई गई विभाजनकारी राजनीति का परिणाम है, स्पष्ट रूप से इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है और मणिपुर की घटनाओं की पृष्ठभूमि में सभी के लिए एक चेतावनी है कि अगर भाजपा शासन को जारी रहने दिया गया तो भविष्य में क्या होगा। भाकपा हिंसा और आगजनी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग करती है। भाकपा सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने और भारत की एकता और सांझी संस्कृति को संरक्षित करने की भी अपील करती है। पार्टी सभी भारतीयों से यह भी अपील करती है कि उन्हें नफरत, भय और हिंसा की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए, जो आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि में भाजपा–आरएसएस की राजनीति का मुख्य मुद्दा होगा।

क्यूबा को आतंकवादी देशों की सूची से हटाने की मांग

हरनाम सिंह

इंदौरः क्यूबा पर आतंकवाद फैलाने का आरोप झूठा है। इस देश में पारदर्शी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। कोविड–19 एवं हर तरह की वैश्विक त्रासदी के दौरान क्यूबा के चिकित्सकों ने पीड़ित मानवता की सेवा की है। ऐसे देश को आतंकवादियों की सूची में शामिल करना उचित नहीं है।

ये विचार व्यक्त किए अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन (एप्सो) के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार ने, वे एप्सो की इंदौर इकाई द्वारा क्यूबा क्रांति के दौरान सेंटियागो में मोंकाडा बैरक्स पर हमले की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में आयोजित गोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यूबा में जमींदारी प्रथा थी, किसानों का शोषण होता था। क्यूबा क्रांति के नायक फिडेल कास्त्रो ने भूमिहीनों में जमीन का वितरण किया। देश के संसाधनों को का उपयोग अपनी जनता की भलाई के लिए किया। क्यूबा के समाजवादी समाज की ओर बढ़ते कदमों से नाराज अमेरिका ने इस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को आतंकवादी देशों की सूची में डाल दिया है। वह अन्य देशों को क्यूबा से कारोबार करने से रोकता है।

अरुण कुमार ने कहा कि कोविड–19 काल के दौरान वहां के चिकित्सा वैज्ञानिकों ने तीन तरह की वैक्सीन विकसित की थी जो 90 प्रतिशत तक सफल प्रमाणित हुई। लेकिन अमेरिका के दबाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन्हें मान्यता देने से इनकार कर दिया। बावजूद इसके विश्व के 56 देशों ने क्यूबा पर भरोसा जताया और उससे वैक्सीन खरीदी, इनमें अमेरिका का मित्र इटली भी था। क्यूबा ने प्राकृतिक आपदा से घिरे अनेक देशों में अपने चिकित्सकों को भेजकर मानवता की सेवा की है। ऐसे देश को आतंकवादियों की सूची में रखना गलत है।

अरुण कुमार ने कहा कि क्यूबा के जननायक कास्त्रो की हत्या के 600 प्रयास किए गए, लेकिन दुश्मन कभी सफल नहीं हुए। उन्होंने विश्व शांति में भरोसा रखने वालों से अनुरोध किया कि वे क्यूबा को आतंकवादी देशों की सूची से हटाने की मांग करें।

एप्सो के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी ने क्यूबा क्रांति की पहली कोशिश, जिसे 'मोंकाडा बैरक्स पर हमले' के नाम से जाना जाता है, की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फिदेल कास्त्रो ने 1953 की 26 जुलाई को 150 साथियों के साथ मिलकर क्रांति का उद्घोष किया था। उन्होंने सैंटियागो शहर में मौजूद तत्कालीन तानाशाह बटिस्टा की फौजी छावनी मोंकाडा बैरक्स पर हमला किया था

लेकिन वे असफल रहे, गिरफ्तार हुए। उन्होंने अदालत में भगत सिंह की तरह स्वयं पैरवी की और पैरवी करते हुए 'इतिहास मुझे सही साबित करेगा' शीर्षक का विश्वप्रसिद्ध भाषण दिया। दुनियाभर से उनकी रिहाई के लिए समर्थन जुटा और 22 माह के कारावास पश्चात वे और उनके साथी रिहा हुए। बाहर आकर उन्होंने फिर क्रांति की योजना बनाना शुरू कर दिया और पहली गलती से सबक लेकर अंततोगत्वा 1959 में वहां कामयाब क्रांति को अंजाम दिया। विनीत ने कहा कि इस अर्थ में पहली क्रांति को नाकाम क्रांति नहीं, बल्कि कामयाबी की ओर बढ़ा पहला कदम कहना चाहिए क्योंकि हर नाकामयाबी, कामयाबी की दिशा में बढ़ा हुआ एक कदम होती है।

अर्थशास्त्री जया मेहता ने कहा कि सोवियत खेमे के टूटने के बाद यह प्रचारित किया जाने लगा था कि अब समाजवाद समाप्त हो गया और पूंजीवाद में आजादी अधिक है। लोग समाजवादी व्यवस्था के लाभों को भूल गए। कास्त्रो ने लैटिन अमेरिकी देशों की जनता को साथ में लेकर साम्राज्यवाद का विरोध किया और विपरीत परिस्थितियों में समाजवाद की रक्षा की। उन्होंने अपने देश में जैविक खेती के क्षेत्र में मिसाल कायम की। क्यूबा क्रांति की रक्षा करना विश्व के सभी शांतिप्रिय नागरिकों का कर्तव्य है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हरनाम सिंह ने कहा कि अमरीकी साम्राज्यवादियों को चुनौती देने वालों में क्यूबा क्रांति के जननायक फिदेल कास्त्रो, चे गुएवारा के अलावा वियतनाम के हो ची मिन्ह सदैव युवाओं को रोमांचित करते रहे हैं। इन्होंने अमेरिकी साम्राज्यवाद का डट कर विरोध किया था। इन देशों ने समाजवाद के स्वप्न को जीवित रखा है।

विषय का प्रवर्तन करते हुए एप्सो इकाई के अरविंद पोरवाल ने कहा कि 26 जुलाई का दिन क्यूबा के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 1953 में इसी दिन क्रांति की नाकाम कोशिश हुई थी। क्रांतिकारियों ने असफलता से सबक सीखकर 1 जनवरी 1959 को क्रांति को सफल बनाया था।

गोष्ठी में चुन्नीलाल वाधवानी, विजय दलाल ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर एप्सो इकाई के संरक्षक एवं पूर्व सांसद कल्याण जैन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आभार माना रामस्वरूप मंत्री ने।

बीकेएमयू के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों का आह्वान

पटना, 30 जुलाई 2023: बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन बिहार राज्य परिषद की बैठक रविवार को जनशक्ति भवन में हुई। बैठक में दो से पांच नबम्बर 2023 तक पटना में आयोजित होने वाले बीकेएमयू के15वें राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर दो नबम्बर को गांधी मैदान, पटना में भाजपा हटाओ, देश बचाओ रैली आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता यूनियन के अध्यक्ष व विधायक सूर्यकांत पासवान ने की। बैठक को भाकपा के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय, यूनियन के महासचिव जानकी पासवान,रामलला सिंह, इरफान अहमद, विश्वजीत कुमार, अजय कुमार सिंह, रविंद्रनाथ राय, पुनित मुखिया, अनिल प्रसाद, अर्जुन राम, रामपुकार मुखिया, सुधीर कुमार, रामनारायण यादव, डीपी यादव आदि ने संबोधित किया।

बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली नरेंद्र मोदी की सरकार खेत मजदूरों के अधिकारों पर लगातार हमला कर रही है। मनरेगा के बजट में लगातार कटौती कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को बंद करने की साजिश की जा रही है। केंद्र सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने के उद्देश्य से एक ही झटके में बिहार के 2.25 करोड़ खेत मजदूरों गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षो के कार्यकाल में खेत मजदूरों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। महंगाई आसमान छू रही है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मजदूर पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि खेत मजदूरों को मनरेगा के तहत कार्य नहीं मिल रहा है। बिहार सूखे की चपेट में है। मनरेगा के तहत मजदूरों को साल में कम से कम दो सौ दिन कार्य देने की गारंटी की जाए और मजदूरी प्रत्येक दिन कम से कम 600 रुपये की जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि प्रत्येक महीने पांच हजार रुपये की जाए। गरीब भूमिहीनों को पांच डिसिमिल जमीन दी जाए। उन्होंने बीकेएमयू के 15वें राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी में पूरी मुस्तैदी से जुट जाने का आह्वान किया। बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के महासचिव जानकी पासवान ने कार्य रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि बिहार में खेत मजदूर आंदोलन को तेज किया जाएगा। पांच लाख से अधिक सदस्य बनाये जाएंगे। दो नवंबर को पटना में ऐतिहासिक रैली होगी।

नाकाम डबल इंजन सरकार, मणिपुर में हाहाकार

आर.एस. यादव

जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, उन सरकारों को बड़ी शेखी के साथ प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार कहते हैं। जब राज्यों में विधान सभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री की एक दलील होती है कि केंद्र में तो भाजपा सरकार है ही, राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाएं यानी भाजपा को वोट दें। डबल इंजन की सरकार से उनका आशय अधिक कारगर और कार्यकुशल सरकार से होता है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है और उसका जनाजा निकल रहा है। ''डबल इंजन'' का प्रधानमंत्री का शगूफा निरर्थक साबित हो चुका है।

मणिपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। पुलिस ने कानून व्यवस्था पर से नियंत्रण खो दिया है। राज्य पुलिस द्वारा हिंसा के मामलों की जांच ''सुस्त'' और ''बहुत ही लचर'' है। यह टिप्पणियां अन्य किसी ने नहीं, 1 अगस्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ही की हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर में बेलगाम जातीय हिंसा से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के तौर–तरीके की आलोचना करते हुए यह कहा कि पुलिस ने कानून व्यवस्था पर से नियंत्रण खो दिया है बल्कि सीबीआई को मणिपुर में पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज न करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर अपरान्ह दो बजे सुनवाई करेगा।

मणिपुर जैसा अन्य राज्यों में हो रहा है, यह तर्क ठीक नहीं

मणिपुर में जारी हिंसा के संबंध में 31 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी पारदीवाला और न्यायमूति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यह तर्क ठीक नहीं कि मणिपुर जैसा अन्य राज्यों में भी हो रहा है। पीठ ने उस समय यह टिप्पणी की जब एक हस्तक्षेपकर्ता वकील बांसुरी स्वराज ने कहा: ''महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और केरल में भी हो रही हैं। भारत की सभी बेटियों को सुरक्षा की जरूरत है। कोर्ट कोई मैकेनिज्म बनाते वक्त मणिपुर तक सीमित न रहे।'' इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, ''पूरे देश में महिलाओं से अपराध हो रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे यह कहकर उचित नहीं ठहरा सकते है कि ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में भी हो रही हैं। क्या आप यह कह रही हैं कि या तो सभी के लिए कुछ करें या किसी के लिए कुछ न करें''?

असल में, यह वकील जो तर्क पेश कर रही थी वह उनका नहीं था। यह तर्क तो प्रधानमंत्री मोदी का था जिसे वह अदालत में पेश कर रही थी।

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के पास मणिपुर में हो रही उस हैवानियत के संबंध में कुछ सफाई देते नहीं बन रहा था जो दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराए जाने और दिन–दहाड़े बलात्कार की घटना के सोशल मीडिया पर आ जाने से दुनिया भर के सामने आ गई थी। तब अन्य किसी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जुलाई को कहा था कि सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खासतौर पर हमारी माताओं–बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। अपनी प्रतिक्रिया को मणिपुर की तात्कालिक घटना तक सीमित न रखकर अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों से जोड़ना मणिपुर में होने वाली हैवानियत को हल्का करने की कोशिश के अलावा अन्य कुछ न था। प्रधानमंत्री के इस कथन के बाद भाजपा के नेताओं ने प्रधानमंत्री के इस तर्क को हाथों–हाथ लिया और हर किसी ने अन्य राज्यों में महिलाओं के साथ हुए अपराधों को उछालना शुरू कर दिया जिसका अर्थ इसके सिवा कुछ न था कि मणिपुर में यह हैवानियत हो गई तो क्या हुआ अन्य राज्यों में भी तो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं।

अन्य राज्यों में महिलाओं पर हो रहे अपराधों का उल्लेख कर मणिपुर में हो रही हैवानियत को हल्का कर पेश करने की इस दलील को जिसे असल में प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुनवाई करते हुए पीठ ने मणिपुर में अभी तक दर्ज प्राथमिकियों (एफआईआर) के सिलसिले में अब तक हुई कार्रवाई पर जानकारी मांगी। अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि राज्य की पुलिस मामले की जांच करे क्योंकि पुलिस ने ही तो महिलाओं को वस्तुतः दंगाईयों की भीड़ को सौंप दिया था जिसके बाद उनके साथ हैवानियत हुई।

अदालत ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से पूछा कि अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, पीड़ित लोगों को किस तरह की कानूनी मदद की जा रही है, लोगों के पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है, मणिपुर में कितने जीरो एफआईआर दर्ज किए गए।

(जीरो एफआईआर किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में हुआ या नहीं। मणिपुर में हालात इतने खराब हैं कि जिन लोगों पर जुल्म हुआ है उनमें से अनेक विस्थापित हो गए हैं और जिस इलाके में उनके साथ जुल्म हुआ वह संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नहीं जा सकते। अतः वे विस्थापित होकर जिस स्थान पर हैं, वहीं के निकटतम थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग इतने परेशान और घबराए हुए हैं कि वे अपने साथ हुए जुल्म की एफआईआर दर्ज कराने भी नहीं जा सके होंगे। अतः राज्य में जितनी एफआईआर दर्ज हुई हैं, उनसे कहीं अधिक मात्रा में अन्य मामले होंगे जिनके संबंध में अभी तक जीरो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई हैं।)

पीठ ने पूछा, महिलाओं को घुमाने का यह वीडियो 4 मई को सामने आया था। पुलिस को एफआईआर दर्ज कराने में 14 दिन का समय क्यों लगा और 18 मई को मामला दर्ज किया गया?

पीठ ने पूछा, पुलिस क्या कर रही थी? वीडियो मामले से संबंधित प्राथमिकी दर्ज होने के एक महीने और तीन दिन बीतने के बाद 24 जून को मजिस्ट्रेट को क्यों भेजी गई?

सरकार की तरफ से पेश होने वाले अटॉर्नी जनरल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सरकार के पास ही नहीं है तो अटॉर्नी जनरल के पास कहां से होता?

जिन महिलाओं के साथ हैवानियत का वीडियो सामने आया था उन महिलाओं से जुड़े मामले की जांच केंद्र सरकार ने सीबीआई को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में ऐसी तमाम घटनाओं की जांच के पक्ष में है और वह इसके लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। परंतु आजकल सीबीआई, ईडी और अन्य जांच एजेंसियां जिस प्रकार सरकार की कठपुतलियां बनकर काम कर रही हैं, उसके कारण लोगों का इन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर विश्वास कम हो गया है। संभवतः इसी कारण पीड़ित महिलाएं सीबीआई द्वारा जांच के केंद्र के निर्णय पर आश्वस्त नहीं हैं।

सरकार के भारी दबाव के बावजूद समाचारपत्र भी मणिपुर की घटनाओं के संबंध में सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जनसत्ता (1 अगस्त 2023) कहता है: ''मणिपुर का मामला दरअसल, राज्य सरकार की लापरवाही और केंद्र सरकार की शिथिलता का नतीजा है। अगर सरकारों ने इस मामले पर काबू पाने की कोशिश की होती, तो कोई कारण नहीं कि यह इतने लंबे समय तक चलता रहता और वहां करीब दो सौ लोगों की जान चली जाती हैं, हजारों लोगों को बेघर जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ता है। सर्वोच्च नयायाल ने कहा कि यह मत कहिए कि वहां एक समुदाय के खिलाफ हिंसा हुई, संदेश यह जाना चाहिए कि वहां हर समुदाय के खिलाफ हिंसा से कड़ाई से निपटा जाएगा। लोगों में संविधान के प्रति भरोसा पैदा करना जरूरी है। दरअसल, मणिपुर में पिछले करीब तीन महीने से हिंसा और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, मगर इस पर पूरी दुनिया में कठोर निंदा का सिलसिला तब शुरू हुआ, जब दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का वीडियो प्रसारित हुआ। इस तरह मणिपुर में चल रही सामुदायिक हिंसा को कई लोगों ने उस वीडियो तक सीमित कर दिया है, जबकि पूरी हिंसा को लेकर ढेर सारे सवाल हैं।

''अब अनेक तथ्य प्रकट हैं, जिनसे राज्य सरकार की शह और केंद्र सरकार की उदासीनता उजागर हेाती है। शस्त्रागार से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस आदि का लूट लिया जाना और सरकारों का इस पर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कई सवाल खड़े करता है। विपक्षी दलो ने इन तमाम सवालों को लेकर संसद में जवाब मांगा है, उनके प्रतिनिधि मणिपुर होकर आए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो सवाल पूछे हैं और उच्चाधिकार प्राप्त समिति से इन घटनाओं से संबंधित जांचों पर निगरानी रखने की बात कही है, उससे राज्य सरकार की लापरवाहियों, पक्षपात और हिंसा को नजरअंदाज करने के तथ्य और स्पष्ट हो सकेंगे। मणिपुर की घटना ने केंद्र सरकार को भी सांसत में डाल दिया है, पूर्वोत्तर के लोगों का भरोसा डिगा है। वहां के दूसरे राज्यों में भी तनाव की आशंका है। ऐसे में वहां तुरंत शांति बहाली के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की उम्मीद की जाती है।''

स्तंभकार शेखर गुप्ता के अनुसार, **''मणिपुर में जो हालात हैं, उन्हें गृहयुद्ध भी कहा जा सकता है''**। वह लिखते हैं कि मणिपुर में ''भाजपा सरकार ने अपनी विभाजनकारी नीति ही जारी रखी और हालात को और भी गंभीर बना दिया। राज्य कितना बंट चुका है इसे समझने के लिए हमें हिंसा की शुरूआत से पहले और उस दौरान भी मुख्यमंत्री के बयानों पर गौर करना होगा। दोनों खेमे हथियारों से लैस हैं लेकिन मुख्यमंत्री एक ही खेमे को उग्रवादी कहते हैं और उसे धमकी देते हैं। जबकि अपने वाले को कोई गैर कानूनी काम न करने की हिदायत भर देते हैं। उनके हथियारों को गैर–कानूनी नहीं बताया जाता, न ही नतीजे भुगतने की धमकी दी जाती है। 29 मई को उनके इस बयान पर गौर कीजिए: ''हमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जो एम–16 और ए.के. 47 जैसे हथियारों से नागरिकों पर हमले कर रहे हैं.....'' उनके दूसरे बयानों से साफ हो जाता है कि वे ''आतंकवादी'' किसे कह रहे हैं। एक से ज्यादा ट्वीट (जिन्हें डिलीट कर दिया गया) में उन्होंने कुकी आलोचकों को ''म्यांमारी'' कहा है। एक आलोचक ने उन्हें जब यह याद दिलाया कि म्यांमार में मैतई भी रहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया कि वे वहां अलग देश की मांग नहीं करते। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह चीन को भी घसीट लाते हैं। 1 जुलाई को उन्होंने बयान दिया–''विदेशी हाथ से इंकार नहीं किया जा सकता.....चीन भी सटा हुआ है''।.. ...(साभार: दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, 25 जुलाई2023)।

पत्रकार राजदीप सरदेसाई लिखते हैं: ''मणिपुर ऐसा राज्य है जिसमें हिंसा की भयावह घटना में अधिकतर एफआईआर या तो ''अज्ञात व्यक्तियों'' के विरूद्ध दर्ज की गई हैं या दर्ज ही नहीं की गई। यह ऐसा राज्य है जिसमें पुलिस थानों से हथियार ''लूट'' लिए गए और पुलिस बेबस बनी रही। यह एक ऐसा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री एक समूह के लोगों को ''आतंकवादी'' करार देते हैं जबकि दूसरे समूह के लोगों द्वारा की जा रही क्रूरताओं की भर्त्सना नहीं करते, और जो वायरल वीडियो सामने आने पर कहते हैं कि ''इस तरह के सैंकड़ों और मामले हुए होंगे''। **नस्ली संघर्ष से ग्रस्त राज्य में पक्षधर सरकार की संलिप्तता ने ही मणिपुर में हालात को विकट बना दिया है।''**

मणिपुर के इतने खराब हालात हो जाने और राज्य में कानून एवं व्यवस्था के बुरी ध्वस्त हो जाने के बावजूद मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा है, इस संबंध में सरदेसाई एक उल्लेखनीय बात कहते हैं: ''यहां पर हम एक असहज का देने वाले सवाल का सामना करते हैं। 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद से नरेन्द्र मोदी को हटाने के विचार को इसलिए त्याग दिया गया था क्योंकि यह समझा गया था कि इसे हिन्दू समुदाय के द्वारा स्वीकार

शेष पेज 14 पर...

परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन समय की मांग

अरुण मित्रा

हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 में हुई परमाणु बमबारी का 78वां साल एक बार फिर से उस भयावह घटना की याद दिलाता है जिसमें ये दोनों शहर नष्ट हो गए, दो लाख से ज्यादा लोग मारे गए और आने वाले कई दशकों तक जीवितों को विकिरण के प्रभाव से पीड़ित होने के लिए छोड़ दिया। इन परमाणु बमों के कारण जिस तरह से इंसान पलभर में विलीन हो गए वह कल्पना से बाहर है। जो जीवित रह गए वे मृतकों से ईष्या कर रहे थे। वे शारीरिक और मानसिक आघात में थे। हिरोशिमा के शांति म्युजियम में हमने अपनी यात्रा के दौरान परमाणु बमबारी के प्रभावों की जिन तस्वीरों को देखा वह भयावह था।

दूसरा विश्वयुद्ध लगभग खत्म हो गया था और यह लगभग निश्चित था कि जापान कुछ हफ्तों से ज्यादा युद्ध में नहीं टिक सकता। जनसंहारक हथियारों के इस्तेमाल का कोई कारण न था। लेकिन अमरीका दुनिया को कहना चाहता था कि अमरीकी सबसे शक्तिशाली हैं। एक शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए एक गुप्त मॉनहेटन प्रोजेक्ट चलाया गया।

आधुनिक विज्ञान ने उस समय तक फिशन रिएक्शन के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के बारे में पर्याप्त जानकारी दे दी थी। 16 जुलाई 1941 को सुबह के पांच बजकर उनतीस मिनट और पैंतालीस सैकेंड पर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के ट्राईनिटि परीक्षण स्थल पर पहले परमाणु बम का विस्फोट किया। इस परमाणु विस्फोट के पीछे भौतिक शास्त्री रॉबर्ट ज्यूलियो ऑपनहेइमर का हाथ था। इस विस्फोट से अभूतपूर्व ऊर्जा निकली–यह 10 सैकेंड से कम समय में टी.एन.टी. के 20,000 टन के बराबर का विस्फोट था। यद्यपि यह बम 30 मीटर ऊंचे स्टील टावर से अधिस्फोटित किया गया था, इस विस्फोट से 40 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा गड्ढा हो गया था। यह गड्ढा चारों ओर से अब तक अनदेखे एक पदार्थ से ढक गया था।

जब पहले परमाणु बम के सफलतापूर्वक अधिस्फोटित किया गया तो ऑपनहेइमर ने दूर से देखा। इसका प्रभाव अकल्पनीय था। ऑपनहेइमर ने बम को विकसित किया लेकिन आगे इसके इस्तेमाल का निर्णय उसके पास नहीं था। वह एक वैज्ञानिक था, जिसका बम के अनुप्रयोग पर कोई नियंत्रण न था इसलिए, जैसा कि हाल में उस पर बनी एक फिल्म में दिखाया गया है कि बाद में उसने एक टिप्पणी में कहा कि विस्फोट के बाद उसके दिमाग में हिन्दू धर्मग्रंथ भागवत गीता के ये शब्द आए: ''अब मैं मृत्यु बन गया हूं, विश्व का विनाश्क''। यह एक सबक है वैज्ञानिकों के लिए कि वे ऐसी चीजों में न लगें जिनका इस्तेमाल नुकसानदायी हो सकता है।

यह स्पष्ट हो चुका है कि हथियारों की होड़ में जनसंहार का यह हथियार जुड़ जाएगा। सोवियत यूनियन ने अपना पहला परमाणु हथियार परीक्षण 29 अगस्त 1940 को सेमीपलाजिंस्क में किया था। पहले परमाणु अभिस्फोटन के विकिरण प्रभाव के नए अध्ययन के अनुसार विकिरण अभिस्फोटन के दस दिनों के अंदर 46 राज्यों में पहुंच गया था। वर्तमान में परमाणु हथियारों वाले नौ देश हैं। कई अन्य देश हैं जिनके पास इस तरह के हथियारों को विकसित करने की क्षमता है। पृथ्वी पर लगभग 1300 परमाणु शीर्ष विस्फोटक हैं।

दुनिया हालांकि मौसम परिवर्तन और परमाणु हथियारों के दोहरे खतरों के प्रति काफी सचेत है। परमाणु युद्ध निवारण से संबद्धित अन्तरराष्ट्रीय भौतिक शास्त्रियों (आईपीपीएनउब्ल्यू) की न्यूक्लियर फेमाइन के नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में अनेक वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर कहा कि तथाकथित 'सीमित' या 'क्षेत्रीय' परमाणु युद्ध न तो सीमित होंगे और न ही क्षेत्रीय। ''एक युद्ध में यदि विश्व के परमाणु हथियारों के 1/20 हिस्से का अभिस्फोटन भी मौसम, विश्व खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और जनजीवन को बर्बाद कर देगा। अकाल और अशांति लाखों, शायद करोड़ों लोगों की मृत्यु होगी भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध में। विश्व परमाणु हथियारों के 3 प्रतिशत से भी कम का इस्तेमाल दुनिया के हर तीसरे व्यक्ति को मार सकता है, साथ ही औसतन वैश्विक तापमान लगभग 1 .3 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। अमरीका और रूस के बीच पूर्ण परमाणु युद्ध दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग दो सालों में मारे जाएंगे। हजारों सालों के मानवीय श्रम से निर्मित आधुनिक सभ्यता का यह अंत हो सकता है।

''न्यूक्लियर फेमाइन'' रिपोर्ट परमाणु देशों के बीच व्यापक तनाव के दौरान आई है और रिपोर्ट चेतावनी देती है कि परमाणु युद्ध के इतने निकट हम पहले कभी नहीं थे। यह खतरा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद कई गुना बढ़ गया है। अमरीका और नाटो की स्पष्ट भागीदारी उनके प्रभाव क्षेत्र को फैलाने की मंशा दिखाती है। वास्तव में वारसा संधि के विलयन के बाद इसी तरह नाटो का विलयन वैश्विक शांति को मजबूत करने में मदद करता।

यह मानवजाति के लिए एकजुट होने का समय है ताकि ये घटनाएं विनाशकारी रूप न ले सकें। यह एक मिथक है कि परमाणु हथियार युद्ध निवारक के जैसे काम करता है इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है। यहां तक कि यदि परमाणु हथियार देश इन हथियारों को इस्तेमाल नहीं करने का निर्णय लेते हैं फिर भी तकनीकी गड़बड़ विनाश कर सकती है। इससे भी बढ़कर इन हथियारों के उत्पादन पर, उनकी तैनाती और चौकसी पर, उनके रख–रखाव पर होने वाले व्यय का असर हमारे संसाधनों पर पड़ रहा है अन्यथा यह व्यय स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सामाजिक जरूरतों पर किया जा सकता है। यह कोई बुद्धिमानी नहीं है कि पहले नुकसान होता देख लें फिर बाद में उस पर रोएं। इनका निवारण हमेशा ही एक बेहतर रास्ता है।

परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए दुनिया भर में अन्तरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई आंदोलन चल रहे हैं। मेडिकल पेशेवर आईपीपीएनडब्ल्यू के बैनर तले एकजुट हुए हैं दुनिया को परमाणु हथियारों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताने के लिए। परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अन्तरराष्ट्रीय अभियान (आईसीएएन) में 650 सहयोगी संगठन हैं जो कि परमाणु हथियार उन्मूलन के लिए लॉबिंग और एडवोकेसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। वास्तव में उनके सघन काम के कारण जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली द्वारा परमाणु हथियारों के प्रतिबंध पर संधि पारित हुई थी। विश्व शांति परिषद और पगवाश जैसे अन्य संगठन इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

अन्तरराष्ट्रीय परमाणु विरोधी आंदोलन ''नेवादा–सेमे'' संयुक्त रूप से परमाणु अभिस्फोटन के प्रभाव पर जागरूक कर रहे हैं, संस्कृतियों के पुनर्मेल को बढ़ावा देने, शांति के विचारों के व्यवहार में लाने, वैश्विक चेतना के उभार के उद्देश्य के लिए सुलेइमेनव ओ. के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इन सभी आंदोलनों का एक साझा लक्ष्य दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने का है। परमाणु हथियार प्रतिबंध समझौता एक आशा है जो कि सामूहिक प्रयासों से पूरी हो सकती है।

भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बैनर तले शांति आंदोलन का अग्रदूत रहा है। भारत के लिए फिर से राजनीतिज्ञता दिखाने का समय है।

शहीद ऊधम सिंह का शहीदी दिवस

पानीपत, 31 जुलाई 2023: अमर शहीद ऊधम सिंह के 83वें शहीदी दिवस के अवसर पर स्थानीय भगत सिंह स्मारक सभागार में यादगार सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता पवन कुमार सैनी और संचालन सीपीआई के जिला सचिव पवन कुमार सैनी ने किया। सभा का आयोजन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पानीपत शाखा ने किया।

सीपीआई के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप ने शहीद उधम सिंह के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियावाला बाग नरसंहार को अपनी आंखों से देखा और 19 वर्ष के युवा उधम सिंह ने नरसंहार के दोषियों को मौत के घाट उतारने की प्रतिज्ञा ली।

जिला सहायक सचिव राम रतन एडवोकेट ने कहा कि शहीद ऊधम सिंह ने अंग्रेजी शासन से देश को आजाद कराने के साथ साथ सामाजिक दासता एवं आदमी के द्वारा आदमी के शोषण के खिलाफ लडाई में अपना जीवन बलिदान किया था। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने 21 साल बाद इंग्लैण्ड में जाकर माइकेल ओ डायर को लंदन में गोलियों से भून कर जलियावाला बाग नरसंहार का बदला लिया। जिला सचिव पवन कुमार सैनी ने कहा कि आज शहीद ऊधम सिंह सहित स्वतंत्रता सैनानियों के विचारों को जनता में प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर माम चंद सैनी, जितेन्द्र पाल सैनी, गुंजन मेहता एडवोकेट, डॉ. रमाकांत, श्यामलाल बैरागी, भूपेन्द्र कश्यप, पराग अग्रवाल, अजीज खान, सतीश यादव, मजदूर नेता अशोक पंवार, संजय कुमार छात्र नेता रुपेश सैनी आदि ने शहीद उधम सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किये और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

इंडिया का विचार...

पेज 1 से जारी...

आरएसएस–भाजपा हिन्दुत्व क्रोनवादी एजेंडे पर जो करारी चोट की, उसका पता चलता है।

जिन ताकतों ने ''इंडिया'' का गठन किया है उनके पास ब्रिटिश उपनिवेशवाद से देश को आजाद कराने की एक शानदार विरासत है। इन ताकतों ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सूत्रपात किया, उसका निर्माण किया, उसे मजबूत किया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। ''इंडिया'' में शामिल ताकतों ने सामाजिक भेदभाव, भाषाई उन्माद और संघात्मकता विरोधी राजनीति के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन ताकतों को देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों एवं युवाओं का विश्वास हासिल है। अपनी हताशा–निराशा में प्रधानमंत्री ने इस गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। उन्हें वामपंथी एवं देशभक्त ताकतों के इतिहास और स्वयं उनके संगठन आरएसएस के इतिहास, दोनों के प्रारंभिक इतिहास को याद दिलाए जाने की जरूरत है। देशभक्त ताकतों ने अंग्रेजी गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए अपना खून–पसीना बहाया जबकि आरएसएस स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध कर अपने आकाओं को खुश कर उनकी वफादारी में लगा था। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने एक मजबूत, समावेशी और सौहार्दपूर्ण देश की परिकल्पना की थी जिसकी बुनियाद में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय था। सांप्रदायिक फूटपरस्ती, जाति पदानुक्रम एवं लैंगिक दमन को बढ़ावा देकर आरएसएस इस विचार के विपरीत काम कर रहा है। देश को नफरत से मुक्त करने और सामाजिक भाईचारा पैदा करने के लिए ''इंडिया'' का गठन किया गया है। ''इंडिया'' सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर न्याय को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़संकल्प है। एकताबद्ध होकर हम जीत हासिल करेंगे।

मणिपुर के सवाल पर देशभर में विरोध प्रदर्शन

ग्वालियर, 25 जुलाई 2023: मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार, हिंसा,सामूहिक बलात्कारों के खिलाफ भाकपा, माकपा, एसयूसीआई, सीपीआई (माले) ने विरोध कर पुतला दहन किया। का विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य एवं ग्वालियर जिला सचिव कौशल शर्मा एडवोकेट ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मणिपुर में सत्ता के संरक्षण में आदिवासियों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार, हिंसा,हत्याओं के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) एवं सीपीआई (माले) के संयुक्त आव्हान पर फूल बाग ग्वालियर में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया।

विरोध प्रदर्शन में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए बलात्कार के आरोपियों को फांसी दो, राज्य में शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करो, आदिवासियों पर अत्याचार बन्द करो, मणिपुर भाजपा सरकार और केन्द्र सरकार मुर्दाबाद, विभाजन की राजनीति बंद करो, फासीवाद मुर्दाबाद, सांप्रदायिक और जातिगत द्वेष फैलाना बंद करो की नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन एवं मणिपुर हिंसक सरकार का पुतला दहन किया गया।

इस अवसर पर भाकपा नेता कौशल शर्मा एडवोकेट, संजीव राजपूत, माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) रचना अग्रवाल, रूपेश जैन, सीपीआई (माले) के विनोद रावत, सीटू नेता रामविलास गोस्वामी, एटक नेता रमेश सविता, अभा किसान सभा के अशोक पाठक, खेत मजदूर यूनियन रामबाबू जाटव,ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के एडवोकेट रविंद्र सरवटे, सावित्रीबाई फुले संगठन की एडवोकेट यशोधरा ने मणिपुर में सत्ता के संरक्षण में महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, वंचित तबकों पर किए जा रहे अत्याचारों की कड़ी भर्त्सना करते हुए पिछले 80 दिनों से अशांति का माहौल है। सरकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही ना करने के कारण हिंसा और बढ़ रही है। मणिपुर में सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं के यौन अपराधों को लेकर है जिसमें उन्हें निर्वस्त्र किया गया और घुमया गया। जिसका वीडियो वायरल होने से पूरा देश स्तब्ध हो गया है। अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जिस पर वक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए मणिपुर में शीघ्र शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से त्यागपत्र देने की मांग की गई है। आज के विरोध प्रदर्शन व आमसभा का संचालन कौशल शर्मा एडवोकेट ने किया।

इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी एवं जन संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए।

सागर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वावधान में मणिपुर में महिलाओं के साथ घटित नृशंस घटनाओं के विरुद्ध पार्टी के राज्यव्यापी अव्हान के तहत आज 25 जुलाई को सागर के रजा तिगड्डे पर अन्य नागरिक समूहों के साथ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में संयुक्त किसान सभा ने भी अपनी हिस्सेदारी की।

भाकपा के राज्य सचिवमंडल से अजित जैन, और जिला सचिव राहुल भायजी ने मणिपुर की महिलाओं के प्रति बर्बर कृत्य पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि विगत दिनों मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार का वीडियो वायरल होने से देश स्तब्ध है, सारा देश शर्मसार हुआ है। मणिपुर के आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, और जमीन पर कब्जा जमवाने की भाजपाई साजिश ने जातिय संघर्षो को हवा दी है। संघर्षो के दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं और मणिपुर में भयावह हिंसा, हत्या, और लूट का दौर चल रहा है। सरकार में काबिज संघी भाजपाई सत्ता के नशे में डूबे हुए हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। गूंगी–बहरी सत्ता को पिछले दो महीने से ज्यादा समय से वैकल्पिक मीडिया, विपक्ष, मणिपुर से बाहर रहने वाले वहाँ के नागरिक और तमाम सिविल सोसाइटी ने ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। सरकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने के कारण हिंसा बढ़ी। हिंसा में महिलाओं को निशाना बनाया जाता रहा, उनके सामूहिक बलात्कार हुए, उनकी हत्याएं की गई, सरकार को मानवाधिकार कार्यकर्ताओ ने स्थिति की भयावहता के संदेश सरकार को पहुँचाये, परंतु भाजपाई राज्य और केंद्र सरकार अपनी हिंदुत्व की नीति को गुजरात की तरह साकार करने में लगी रही। सरकार के संरक्षण में मैतेई हिन्दू, मणिपुर के आदिवासियों पर जुल्म, अत्याचार करते रहे। उन्होंने कहा कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त होना चाहिए, पर चूंकि वहां भाजपा की सरकार है, तो कोई कार्यवाही नहीं। आज हमारे देश का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है।

रजा तिगड्डे पर आयोजित प्रदर्शन में भाकपा के चंद्र कुमार जैन, हरजू अहिरवार, राजेन्द्र, स्वदेश सनकत, आनंद पथरोल, प्रवेंद्र, हेमंत, दीपक ज्ञान, मुन्ना सनकत, आशीष, संदीप, समेत संयुक्त किसान सभा के संदीप ठाकुर, अभिनव सेन, सूर्यप्रताप ठाकुर आदि शामिल हुए। प्रदर्शन में उद्वेलित जनों ने 'जाति आधारित विभाजक नीति बन्द करो', 'मणिपुर सरकार–बर्खास्त करो', 'महिलाओं पर अत्यचार बन्द करो', 'मोदी तुम जवाब दो, मौन क्यों–मौन क्यों' नारे लगाए गए।

सारण (बिहार)

मणिपुर में जारी हिंसा के खिलाफ भाकपा कार्यकर्ताओं में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका और वहां के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की।

पिछले कई माह से जारी मणिपुर में हिंसा, महिलाओं के साथ अत्याचार एवं बलात्कार के खिलाफ भाकपा कार्यकर्ताओं छपरा शहर के भगवान बाजार में प्रतिवाद मार्च निकाला एवं मोदी का पुतला दहन करते हुए मणिपुर में अविलंब शांति बहाली की मांग की। कार्यकर्ता स्थानीय श्याम देव नगर से पुतला के साथ प्रतिरोध मार्च विभिन्न मार्गो से होते हुए भगवान बाजार माल गोदाम रोड पर पहुंचें एवं मोदी सरकार का पुतला दहन करते हुए रोशपूर्ण प्रदर्शन प्रदर्शन किया। नेतृत्व जिसका नेतृत्व जिला प्रभारी सचिव रामबाबू सिंह एवं नगर सचिव सुरेश वर्मा ने की।

मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी जिला सचिव रामबाबू सिंह ने कहा कि पिछले कई माह से मणिपुर जल रहा है 60 हजार आदिवासियों के घर जला दिए गए 120 और औरत मर्द आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया। महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया बर्बर जुल्म किए गए लेकिन मोदी विदेश में घूमते रहे जो देश को शर्मसार करने वाली धब्बा है इसकी निंदा करते हुए कामरेड सिंह ने अविलंब शांति बहाल करने की मांग की अन्यथा भाकपा तीव्र आंदोलन को मजबूर होगी।

इस आयोजन में मुख्य रूप से प्रभारी जिला सचिव रामबाबू सिंह सुरेश वर्मा, भदई राम, शिवनाथ राय, रमेश ठाकुर, जवाहर मिश्रा, रतन प्रकाश सिंह, दिलीप बर्मा, डाक्टर राम एकबाल प्रसाद आदि नेताओं ने शिरकत की और मठिया मोहल्ले में पानी बिजली स्वास्थ्य सेवा शिक्षा आदि की समुचित मांग करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मणिपुर में शांति बहाली की मांग की।

अंतिम सांस तक देश की आजादी और समाजवाद के लिए संघर्षरत रहे मौलाना बरकतुल्ला

एक घुमक्कड़ क्रांतिकारी की जीवनगाथा

डॉ. गिरीश

भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता, क्रान्तिकारी तथा गदर पार्टी के नेता अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला–आगे चलकर मोहम्मद बरकतुल्ला नाम से जाने गये। उनका जन्म 7 जुलाई 1854 को मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य के एक संपन्न घराने में हुआ था। उन्होने यूरोप, अमेरिका, जर्मनी, जापान, अफगानिस्तान और मलाया आदि देशों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरूद्ध भारतीयों के बीच बगावत की अलख जगायी। इतना ही नहीं उन्होने विश्व के बड़े नेताओं जिनमें सोवियत संघ के क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट नेता ब्लादीमीर इल्यीच लेनिन शामिल हैं, से हिंदुस्तान की आजादी के लिए मदद मांगी। भारत की स्वतन्त्रता के लिए उन्होने देश–विदेश के समाचार पत्रों में क्रान्तिकारी लेख लिखे और ओजस्वी भाषण दिये। स्वतंत्र भारत के लिये बनी पहली निर्वासित सरकार के वे प्रधानमंत्री बनाये गये।

सोवियत रूस पहुँचने और वहां की 1917 की सर्वहारा क्रान्ति के विश्व के उत्पीड़ित जनों और परतंत्र राष्ट्रों के प्रति संवेदी भाव को देख वे इतने प्रभावित हुये कि रूस के ग्रहयुद्ध के दिनों में वे क्रान्ति के पक्ष में अलख जगाने वाले महान योद्धा के रूप में उभरे। उन्होने बार बार कहा कि परतंत्र राष्ट्रों की स्वाधीनता के संघर्षो को जारी रखने के लिये रूस की समाजवादी क्रान्ति की रक्षा जरूरी है। इसके लिये उन्होंने दुनियाँ के विभिन्न समूहों को संबोधित किया और मुस्लिम समाज को लोकतान्त्रिक बनाने तथा आजादी के आंदोलन में भागीदार बनाने को अथक प्रयास किया।

लेकिन यह बिडम्बना ही है कि भारत की आजादी के लिए इतना सब कुछ करने वाला यह योद्धा भारत को स्वतंत्र देखने के लिए जीवित नहीं रह सका। 20 सितंबर 1927 को अमेरिकी शहर सैन–फ्रांसिस्को में उनकी मृत्यु हो गयी। उनको घुमक्कड़ क्रान्तिकारी कहा जाये तो उचित ही होगा। उनकी यादगार को अक्षुण्ण बनाने और उनके प्रति क्रतज्ञता का इजहार करते हुये 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदल कर बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कर दिया गया।

उनके प्रारम्भिक जीवन के बारे में पता चलता है कि मौलाना बरकतुल्ला ने भोपाल के सुलेमानियां स्कूल से अरबी और फारसी की माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही उन्होने यहाँ से हाई स्कूल तक की अंग्रेजी शिक्षा भी हासिल की। शिक्षा के दौरान ही उन्हें उच्च शिक्षित और अनुभवी मौलवियों और अन्य विद्वानों से मिलने और उनके विचारों को जानने–समझने का मौका मिला। शिक्षा समाप्त होने के बाद वे उसी स्कूल में अध्यापक हो गये।

यहीं पर अध्यापन करते हुये वे शेख जमालुद्दीन अफगानी से काफी प्रभावित हुये। शेख साहब उस समय सारी दुनियाँ के मुसलमानों के बीच एकता और भाईचारा कायम करने के लिये दुनियाँ का दौरा कर रहे थे। इस दरम्यान बरकतुल्ला के माता पिता की मृत्यु हो गयी थी। एकमात्र बहन का विवाह हो चुका था। अब मौलाना नितांत अकेले रह गये। उन्होने भोपाल छोड़ दिया और बंबई आ गये। उन्होने खंडाला और बंबई में ट्यूशन पढ़ाने के साथ अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने 4 साल में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा हासिल कर ली और 1887 में आगे वाली पढ़ाई के लिये इंग्लेंड चले गये।

इंग्लेंड में उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान राजनीति की ओर उनका झुकाव हुआ और शीघ्र ही उनका ध्यान भारत की स्वतन्त्रता की ओर आकर्षित हुआ। संयोगवश श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि वहां भारत की आजादी के लिए क्रान्तिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जुटे थे, से उनकी भेंट हुयी और भारत की आजादी के प्रति उनके विचार और मजबूत हुए। अतएव वे पढ़ाई छोड़ कर भारत लौट आए। 1905 के बंग भंग आंदोलन की तीव्र आंधी से प्रभावित हो कर वे क्रान्तिकारी दल में शामिल हो गए और मुसलमानों में स्वतन्त्रता की भावना जगाने के काम में जुट गये। उनके प्रयासों से बहुत से मुसलमान बंग भंग आंदोलन में शामिल हुये थे।

कुछ दिनों बाद मौलवी बरकतुल्ला ने अनुभव किया कि वह भारत में रह कर उन कामों को नहीं कर सकेंगे जिन्हें कि वे करना चाहते हैं। यदि भारत को स्वतंत्र कराना है, तो विदेशों में जा कर अलख जगानी होगी। फलतः वे जापान चले गए। वहाँ उन्होने जापानी भाषा का अध्ययन किया और टोक्यो विश्वविद्यालय में हिन्दुस्तानी का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। वहाँ उन्होने 'अल इस्लाम' नाम का पत्र भी प्रकाशित किया जिसमें भारत की स्वतन्त्रता के संबंध में लेख प्रकाशित होते थे। अल इस्लाम मुसलमानों में अधिक पढ़ा जाता था। उसकी प्रतियाँ विदेशों के साथ साथ भारत में भी आती थीं। अतएव वे अंग्रेजों की आँखों की किरकिरी बन गये। अंग्रेज सरकार ने जापान सरकार पर दबाव डाला कि वह या तो बरकतुल्ला को गिरफ्तार करे, या उन्हें जापान से बाहर निकाल दे। फलस्वरूप बरकतुल्ला को जापान छोड़ देना पड़ा।

बरकतुल्ला जापान से अमेरिका चले गये। उन दिनों गदर पार्टी भारत की स्वतन्त्रता के लिए जोरों से काम कर रही थी। लाला हरदयाल भी वहीं

पर थे। बरकतुल्ला भी गदर पार्टी में शामिल हो गये और लाला हरदयाल जी के साथ मिल कर काम करने लगे। अंग्रेज सरकार के आग्रह पर अमरीकी सरकार ने लाला हरदयाल को गिरफ्तार कर लिया। परंतु बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। छूटने पर हरदयाल जी जिनेवा चले गये जहां से कुछ दिन बाद बर्लिन पहुँच गये। वहाँ उन्होंने भारत को आजादी दिलाने के उद्देश्य से इंडियन नेशनल पार्टी नामक संस्था का गठन किया। वहाँ केरल में जन्मे आजादी के योद्धा एवं क्रान्तिकारी चम्पक रमण पिल्लई भी उनके सहयोगी थे। बरकतुल्ला भी अमेरिका से बर्लिन आ गये और इंडियन नेशनल पार्टी में काम करने लगे।

उन दिनों राजा महेन्द्र प्रताप भी बर्लिन में ही थे। जर्मनी की सरकार ने राजा महेन्द्र प्रताप को एक संदेश देकर अफगानिस्तान भेजा। मौलवी बरकतुल्ला भी दुभाषिए के रूप में अफगानिस्तान भेजे गये थे। राजा महेन्द्र प्रताप जब इस्तांबूल पहुंचे, तो वहीं उनकी बरकतुल्ला से भेंट हुयी। यह उनकी और बरकतुल्ला की पहली भेंट थी। आगे चल कर ये दोनों ही देशभक्त एक–दूसरे के अनन्य और परम विश्वासपात्र साथी रहे।

भारत में ब्रिटिश आधिपत्य को प्रतीकात्मक रूप से नकारते हुये भारत भूमि को आजाद कराने में जुटे मुक्ति योद्धाओं के एक ग्रुप ने काबुल में 1915 में स्वतन्त्र भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया। राजा महेन्द्र प्रताप को उसका राष्ट्रपति और प्रोफेसर मोहम्मद बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऊबेदुल्ला सिन्धी गृह मन्त्री बने। काबुल में स्थापित इस सरकार का उद्देश्य उत्तर भारत से हमला कर भारत से अंग्रेजों को भगाना था मगर प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया और प्लान कामयाब नहीं हुआ।

महान अक्तूबर सोशलिस्ट क्रान्ति के तत्काल बाद से ही भारत के प्रवासी राजनेताओं ने मॉस्को आना जाना शुरू कर दिया था। वे घृणित ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संयुक्त कार्यवाहियों के संबंध में लेनिन से मिल कर विचार करना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत से तमाम खतरों को देखते हुये भारतीय क्रान्तिकारियों को विशिष्ट हिम्मत एवं दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती थी। रूस के नए शासन को ब्रिटिश हुकूमत पचा नहीं पा रही थी। 1917 के दिसंबर में उसने दो सशस्त्र जत्थों का गठन किया और उन्हें सोवियत ट्रान्सकाकेशियन गणराज्यों और मध्य एशिया (तुर्किस्तान) में भेजा। उनका उद्देश्य उन इलाकों से सोवियत सरकार को उखाड़ कर कब्जों से मुक्त कराना और अक्तूबर क्रान्ति के वैचारिक तूफान को एशिया और भारत तक पहुंचने से रोकना था।

इस दरम्यान काबुल में रह रहे प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों पर ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की खास निगाह रहती थी। अफगानिस्तान ब्रिटिश हुकूमत के अधीन न था अतएव इन प्रवासी क्रान्तिकारियों के लिये यह एक सुरक्षित पनाहगाह था। आज विश्वपटल पर भले ही अफगानिस्तान की भूमिका नकारात्मक हो, लेकिन अतीत में उसकी कबीलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था ने प्रगतिशील भूमिका निभाई है।

फरबरी 1919 में अफगानिस्तान में जब आमिर अब्दुल्लाह खान ने सत्ता संभाली तो उसने ब्रिटिश साम्राज्य को अपना शत्रु घोषित कर दिया। उसने एक घोषणापत्र जारी कर पूरब के सभी लोगों के प्रतिनिधियों, जो उपनिवेशवादी प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करते और आजादी के लिये लड़ने को तैयार हैं, अफगानिस्तान आने का आह्वान किया। इस विशिष्ट काल और परिस्थिति में मोहम्मद बरकतुल्ला काबुल से मॉस्को आने वाले पहले क्रान्तिकारी थे।

भारत के नेशनल आरकाइव्स में उपलब्ध रिकार्ड्स से पता चलता है कि ब्रिटिश हुकूमत अपने औपनिवेशिक साम्राज्य के लिये बरकतुल्ला को एक बहुत खतरनाक शत्रु मानती थी और अफगानिस्तान में हो या सोवियत रूस में, विभिन्न मिलिट्री एवं राजनैतिक जासूसी सेवाओं द्वारा उन पर गहरी निगरानी रखी जाती थी। वे भारत में प्रवेश न कर पायें, इसकी कड़ी चौकसी रखी जाती थी। सच तो यह है कि आज हम बरकतुल्ला के क्रान्तिकारी क्रियाकलापों के बारे में जितना कुछ जानते हैं, उसका बड़ा भाग इन खुफिया एजेंसियों द्वारा रिकार्ड की गई उनकी गतिविधियों पर आधारित है। ताशकंद में उन पर तथा उनके समूह पर नजर रखने के लिये कई एजेंट नियुक्त किये गये और काशगर (सिन–क्यांग, चीन) में ब्रिटिश काउंसिलर को निर्देश दिये गये कि यदि बरकतुल्ला चीनियों की मदद से अथवा बिना मदद के भारत आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाये।

ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों द्वारा 21 मई 1919 को लंदन से भेजे गये एक नोट से पता चलता है कि प्रथम विश्वयुद्ध के दरम्यान बरकतुल्ला ने संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, ईरान और अफगानिस्तान का दौरा किया था। अफगानिस्तान से वे बुखारा होते हुये समरकन्द और ताशकंद चले गये। ताशकन्द में उन्हें और उनके 15 सदस्यीय समूह को होटल तुर्किस्तान में विशेष रूप से सज्जित आवास दिये गये थे। यहाँ वे सरकार के उच्च पदाधिकारियों और महत्वपूर्ण शख्सियतों से जुड़े थे।

अमेरिकी खुफिया सूत्रों के द्वारा दर्ज रिकार्ड के अनुसार 27 मार्च 1919 को बरकतुल्ला अधिकारियों से प्राप्त अनुमति के बाद अपने सेवक इब्राहीम और एक साथी पूर्व टर्किश युद्ध–बंदी उजुप ड्रिजया बेग सहित 23 विदेशियों के समूह के साथ शहर से रवाना हुये।

इसी खुफिया नोट में कहा गया कि बरकतुल्ला और उनके साथी 18 अप्रैल को मॉस्को पहुँच गये। 1917 से 1946 तक सोवियत राज्य में मिनिस्ट्रीज को कम्मिसारियेट कहा जाता था। बरकतुल्ला और इस समूह का स्वागत वहाँ सोवियत रूस के विदेशी मामलों की कम्मिसारियेट के एक प्रमुख अधिकारी वोज्नेसेंस्की द्वारा किया गया। इस खुफिया नोट के अनुसार बरकतुल्ला की मुलाकात लेनिन, जी वी चिचेरियन, विदेश मामलों के तत्कालीन कम्मिसार,

एल एम कारखान, तत्कालीन डिप्टी कम्मिसार एवं अन्य बोल्शेविक नेताओं से करायी गयी।

यद्यपि बरकतुल्ला के अनुसार उनके इस दौरे का उद्देश्य एक कम्युनिस्ट महाधिवेशन में भाग लेना था, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का विश्वास था कि हो सकता है कि वह गर्मी में किसी समय पामीर के रास्ते भारत आकर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की योजना पर विचार विमर्श करने को वहां आये हों। भारत के क्रांतिकारियों पर निगरानी रखने को नियुक्त अमेरिकी काउंसिल के एक अज्ञात मुखबिर ने दावा किया कि बरकतुल्ला ने उसे बातचीत में बताया था कि वे बोल्शेविकों से मुस्लिम्स के बीच लोकतन्त्र लाने के संघर्ष में मदद चाहते हैं।

अमेरिकी एवं ब्रिटिश जासूस बरकतुल्ला पर लगातार निगरानी रखते थे और उन्होंने उनके निजी सामान की जांच पड़ताल भी की। घटना 1920 की बुखारा की है। इस समय बरकतुल्ला के साथ स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार के राष्ट्रपति राजा महेन्द्र प्रताप भी थे। उन दोनों के सामान की जांच की गयी और उनके दस्तावेजों को चुरा लिया गया।

अक्तूबर क्रान्ति के बाद के प्रारंभिक काल में सोवियत रूस द्वारा पूरब के तमाम लोगों के साथ सहयोगात्मक संबन्ध स्थापित किए जा रहे थे। बरकतुल्ला उनमें महत्वपूर्ण थे। अतएव उनकी गतिविधियां और आवागमन रूस के अन्य भागों तक भी था, खासकर कजान तक। यहां कजान में तातार भाषा के अखबार 'कायजायल आर्मिया' (रेड आर्मी) में 11, मई 1919 को प्रकाशित एक लेख में जानकारी दी गयी थी कि अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान के विशेष दूत के रूप में बरकतुल्ला पहुंच रहे हैं। अखबार के इसी अंक में कहा गया कि 7 मई 1919 को भारतीय क्रान्तिकारी की भेंट लेनिन से हुयी और उन्होंने पूर्व के देशों की स्थिति पर विचार किया तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ अफगानिस्तान के चल रहे संघर्ष को सहयोग प्रदान करने की संभावनाओं पर चर्चा की।

इसके कुछ दिनों बाद 15, मई 1919 को कायजायल आर्मिया ने बरकतुल्ला द्वारा 7, मई 1919 को इजवेस्तिया को दिये गए साक्षात्कार का अनुवाद प्रकाशित किया। बाद में यह सोवियत संघ के अनेक अखबारों में पुनः प्रकाशित हुआ। इन अखबारों में भारत के इस लोकतंत्रवादी, दर्शनशास्त्र और साहित्य के प्रोफेसर को दिल्ली में मुस्लिम लीग के सदस्य और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पेश किया गया था।

अपने साक्षात्कार में प्रोफेसर बरकतुल्ला ने बल दिया "मैं न कम्युनिस्ट हूं, न सोशलिस्ट।" "मेरे जीवन का लक्ष्य ब्रिटिशर्स को एशिया से बाहर करना है। मैं एशिया में यूरोपियन पूंजीवाद का सीधा दुश्मन हूं, जिसके प्राथमिक प्रतिनिधि ब्रिटिश हैं। इस मामले में मैं कम्युनिस्टों से जुड़ा हूं, और इस मामले में हम स्वाभाविक सहयोगी हैं।" उन्होंने कहा कि रूस की सोवियत सरकार द्वारा सभी लोगों से पूँजीपतियों से लड़ने के आह्वान ने मेरे और मेरे मित्रों के ऊपर गहरा असर छोड़ा है। (उस समय के भारतीय क्रान्तिकारी पूंजीपति शब्द का प्रयोग विदेशियों, प्रमुख रूप से अंग्रेजों के लिए किया करते थे।)

बरकतुल्ला ने कहा रुस द्वारा साम्राज्यवादी सरकारों द्वारा थोपी गयी सभी संधियों को ठुकराने तथा सभी छोटे अथवा बड़े लोगों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा

का बहुत गहरा असर पड़ा है। इस कदम ने एशिया के सभी शोषित जनों, पक्षों, जो कि सोशलिस्ट होने से कोसों दूर हैं, सोवियत रूस के इर्द गिर्द एकजुट कर दिया है। ऐसे कदम एशियन क्रान्ति की अनिवार्यता और उसे जल्द अस्तित्व में लाने की पूर्वपीठिका हैं।

रूस के इस नए नारे का अर्थ और परिणाम जल्दी ही ब्रिटिशर्स की समझ में आ गया और उन्होने रूस से भारत को अलग थलग करने को कदम उठाना शुरू कर दिये। उन्होंने मध्य एशिया में मर्व की ओर कदम बढ़ाए, बुखारा से गठजोड़ बनाने की कोशिश की और अन्त में रसियन व्हाइट गार्ड (क्रांति विरोधी समूह) की मदद से फेरगाना फ्रंट बनाया। वे पूर्वी चीन पर रूस के प्रभाव को भी रोकना चाहते थे। बरकतुल्ला ने जोर देकर कहा कि विदेशी भूमि और राष्ट्रों को जीता जा सकता है, लेकिन महान विचारों को कोई नहीं कुचल सकता। और बोल्शेविक विचार भारतीय मजदूरों के दिमाग में पहले ही घुस चुके हैं। बरकतुल्ला और उनके साथियों की 7 मई 1919 को लेनिन के साथ हुयी बैठक, सोवियत रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को पढ़ने, तथा वहां हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों और सोवियत रूस के मजदूर वर्ग के अभूतपूर्व उत्साह को देख–भारतीय लोकतंत्रवादियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। रूस भ्रमण के बाद, बरकतुल्ला लेनिन के अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर आधारित सोवियत सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों के उत्साही समर्थक बन गये। केवल समर्थक ही नहीं, पूरब के देशों में उन सिद्धांतों के उत्साही प्रचारक बन कर उभरे।

जून 1919 में कायजायल आर्मिया में मुस्लिम बंधुओं के लिए प्रकाशित उनके संदेश के द्वारा बरकतुल्ला ने रूस और उसके बाहर के मुसलमानों को समझाया कि सर्वहारा की क्रान्ति से साम्राज्यवादी शक्तियाँ बौखला गयी हैं और वे इस युवा गणतन्त्र के खिलाफ आंतरिक शत्रुओं को हथियारबन्द कर रही हैं तथा कामगारों और किसानों के इस राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से इसके खिलाफ विदेशी हस्तक्षेपों को संगठित कर रही हैं।

1918–1920 के बीच रूस के सिविल वार में प्रतिक्रांतिकारियों के एक नेता ए. वी. कोल्चाक के बारे में बरकतुल्ला ने घोषित किया "मुस्लिम बन्धुओ! कोल्चाक के विरूद्ध संघर्ष सभी उत्पीड़ित राष्ट्रों की मुक्ति के लिए है", यही रूस के मुस्लिमों का मुख्य लक्ष्य है! कोल्चाक के सैनिकों के आगे आने वाले पुलों को तोड़ दो, रेल रोड्स को नष्ट कर दो, कोल्चाक सेना की पोषण लाइन पर हमला करो! ये और इस प्रकार के कदम टर्की, ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की आजादी के समान होंगे! जो इस रास्ते का अनुगमन करेंगे वे ही सही आजादी प्राप्त करेंगे! यही पवित्र मार्ग है! अल्लाह आपका मददगार हो!" (कायजायल आरमिया 15 जून 1919)

यह भावुक अपील एक ओर नवोदित रूसी सर्वहारा क्रान्ति की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के संबन्ध में बरकतुल्ला की साफ समझदारी का प्रमाण है, दूसरी ओर इससे पता चलता है कि साम्राज्यवादी देशों और उनके पिछलग्गुओं से घिरा हुआ सोवियत गणतन्त्र उन दिनों कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। बरकतुल्ला की स्पष्ट समझ थी कि विश्व के परतंत्र राष्ट्रों को आजाद करने के संघर्ष को बल प्रदान करने के लिये वोल्शेविक क्रान्ति की रक्षा आवश्यक है।

1919 के पतझड़ में जब प्रतिक्रान्ति और विदेशी हस्तक्षेपों ने कामगारों– किसानों के राज्य को नष्ट करने की कोशिश की, बरकतुल्लाह ने रूस के सभी कामगारों से दोबारा अपील की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस निर्णायक घड़ी में सोवियत गणतन्त्र को बचाने के लिये हर कोशिश की जानी चाहिये। क्रांति की रक्षा के लिये महिलाओं के योगदान पर भी उनकी नजर थी।

सोवियत रूस की महिलाओं को संबोधित करते हुये बरकतुल्ला ने कहा–

"सोवियत पावर ने महिलाओं को स्वतन्त्रता दी है, इसलिये महिलाओं को वर्तमान सरकार को अपने शत्रुओं से छुटकारा पाने में मदद करनी चाहिये। उन्हें अपने पतियों, पुत्रों और भाइयों से बात करनी चाहिये। उन्हें अपने जीवन और साधनों से क्रान्ति और अपनी आजादी की उपलब्धियों को बचाने से बचना नहीं चाहिये। (कायजायल आरमिया 27, अक्तूबर 1919)।

बरकतुल्ला ने सोवियत रिपब्लिक के पूर्वी भागों के कई दौरे किये, अपने इन दौरों के दौरान उन्होने मजदूरों से सोवियत पावर को बचाने के लिये अपील करते हुये प्रेरणाप्रद भाषण दिये। 1919 के अक्तूबर के मध्य में वे दोबारा कजान गये जहां उन्होने 17 अक्तूबर को एक बड़ी राजनैतिक रैली में महत्वपूर्ण भाषण दिया।

उन्होने कहा "वर्तमान समय स्वर्णिम है" जबकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार खुल कर रख सकता है। मानव लंबे समय से इसका इंतजार कर रहा था। इसे हासिल करने के लिए पूंजीवाद और गरीब दुनियाँ के बीच में अत्यधिक निर्णायक संघर्ष जरूरी था। यह सही है कि आज हम विकराल कठिनाइयों, भूख और गरीबी का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्यारे और अधिक प्रिय बच्चे की चाहत बनी हुयी है। यही बात आजादी के बारे में भी है, यह भी भारी कठिनाइयों से हासिल होती है। लेकिन आजादी को धैर्य और धीरज से ही बनाए रखा जा सकता है।

लेनिन की सरकार की विदेश नीति को एक "अत्यधिक महान और उदार" बताते हुये बरकतुल्ला ने कहा कि चाहे युद्ध का समय हो या शांति का, सोवियत राज्य ने दूसरे देशों के भूभागों पर कभी दावा नहीं किया, और उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया।

उन्होंने आगे कहा "सोवियत राज्य एक शांतिप्रिय राज्य है। "यह सोवियत सरकार के सत्ता में आने के प्रारंभिक दिनों में ही युद्धरत देशों से युद्ध रोकने की अपील से ही सिद्ध हो चुका है, लेकिन इसके दुश्मनों ने उसे हथियार उठाने को मजबूर किया है।

कजाख सरकार के मुखपत्र इजवेस्तिया के मार्च एवं अप्रैल 1920 के कई अंकों में "विल्सन एंड लेनिन" शीर्षक के साथ बरकतुल्ला का एक और लेख प्रकाशित हुआ। इसमें भारत के इस क्रांतिकारी ने लिखाः

"सबसे कम अपेक्षित स्थान पर एक अत्यधिक दूरदर्शी व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जिसने बुराई की मूल जड़ को पकड़ लिया है। रूस की महान अक्तूबर क्रान्ति ने लेनिन को अंतर्राष्ट्रीय अखाड़े के अग्रिम मोर्चे पर ला कर खड़ा कर दिया है, और उन्होंने अपनी भूमिका को उत्कृष्टता से निभाया है। उनका विश्वास है कि अन्याय, गरीबी और पृथ्वी पर युद्धों को तभी रोका जा सकता है जबकि समाज के आधार मौलिक रूप से बदल जाते हैं। जैसे कि रोशनी, हवा एवं वर्षा सभी जीवित प्राणियों के लिए है, उसी तरह प्राथमिक आवश्यकता और विलासिता की वस्तुओं पर समाज के सभी लोगों का सामूहिक स्वामित्व हो...

..

बरकतुल्ला ने कहा–"इस निडर प्रोग्राम ने मानवता की परेशानियों को समाप्त करने वाले और सामाजिक बुराइयों से लड़ने वाले साधनों को यकायक बहुत आगे बढ़ा दिया है। अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले लोगों को इससे अच्छा रास्ता शायद ही मिले..... लेनिन एक ऐसा व्यक्ति हैं जो पूर्व के नायकों से निश्चय ही बहुत आगे निकल चुके हैं।"

"कामरेड लेनिन असली आजादी, समानता और भाईचारे का परचम लहरा चुके हैं। सारी मानव जाति की मुक्ति के लिये हम सबको उस परचम के साथ आ जाना चाहिए। लेनिन का अनुशरण करें, जिन्होंने पूरब के लोगों के दिलों को जीतने को पहल की, और आशा से अधिक सफलता प्राप्त की" बरकतुल्ला ने कहा।

प्रोफेसर बरकतुल्ला नए सोवियत

शेष पेज 15 पर...

मुरादाबाद खेत मजदूर यूनियन का जिला सम्मेलन संपन्न

मुरादाबाद, 30 जुलाई 2023: उप्र खेत मजदूर यूनियन जिला मुरादाबाद का जिला सम्मेलन अमरदीप सिंह व ममता कश्यप के दो सदस्यीय अध्यक्षमंडल की अध्यक्षता में पंचायत भवन, रामराय बसन्त पुर में सम्पन्न हुआ।

उ. प्र. खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री फूलचन्द यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज पूरा देश ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा है किसी भी वक्त दावानल का रुप ले सकता है। भाजपा, आरएसएस सत्ता के लिए देश को नफरत की आग में झोकने के लिए तैयार बैठे हैं चारों तरफ साम्प्रदायिक शक्तियां सौहार्द और भाइचारे को आगा में झोकने का काम कर रही हैं मुल्क के संविधान को तहस–नहस करने में लगी है। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक सभी के सभी संविधान की शपथ लेने के बाद भी उसकी ऐसी–तैसी करने पर आमादा हैं। संविधान की प्रस्तावना के पहले चार शब्द 'हम भारत के लोग' जिसमें सभी धर्मो, पंथों के लोग आते हैं जिसमें विद्यार्थी, नौजवान, किसान, मजदूर, महिला, व्यापारी, आदिवासी, दलित, पिछड़ा सभी आते हैं, सभी की हालत खराब है महिलाओं की हालत सबसे जादा खराब है। उनकी तो आबरू की सुरक्षा की कोई गारण्टी ही नहीं है, प्रधानमंत्री और उनके लो संविधान में वर्णित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को पाखंडवाद कह रहे हैं। इन लोगों का विश्वास के मनुस्मृति में है उसी के बताये रास्ते पर आगे बढ़

फूलचन्द यादव

रहे हैं जिससे संविधान को खतरा पैदा हो गया है डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा रचित संविधान देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है अगर संविधान खत्म कर दिया गया तो डॉ. भीमराव आंबेडकर भी खत्म हो जायेंगे, ऐसी स्थिति में खेत मजदूरों की जिम्मेदारी बनती है कि खेत मजदूरों की लड़ाई लड़ने के साथ ही साथ संविधान को बचाने की लड़ाई भी शिद्दत के साथ लड़नी है तभी संविधान व डॉ. भीमराव आंबेडकर को बचाने का काम किया जा सकता है।

फूलचन्द यादव ने मणिपुर में ज्वलंत सवाल को उठाते हुए कहा कि मणिपुर के हालात बद से बदतर हो गये हैं। जिस देश में कहा जाता है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमन्ते तत्र देवता:' वहाँ पर महिलाओं के साथ हैवानियत की हद तक महिलाओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, बच्चियों से लेकर बूढ़ी महिलाओं की आबरू तार–तार की जा रही है, उनके शरीर को भूखे भेड़ियों की तरह नोंचा–खसोटा जा रहा है ऐसी घटनाएं किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। बेशर्म सरकार आंख मूंदकर तमाशा देख रही है मणिपुर का मुख्यमंत्री बयान देता फिर रहा है और अपनी अक्षमता कबूल करता फिर रहा है कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुयी हैं। कहाँ–कहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक किया जाये, होना तो ऐसा चाहिए था कि सरकार

बर्खास्त कर दी जाती और मुख्यमंत्री को जेल के सीखचों के भीतर डाल देना चाहिए था मणिपुर के कारण पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों के अन्दर आग की लपटें फैल रही हैं जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार की है मणिपुर के ऐसे हालात के लिए भारत सरकार, मणिपुर प्रदेश सरकार, मोदी मीडिया और भाजपा आरएसएस के एण्टी सोशल एलीमेंट का गठबन्धन जिम्मेदार है। इस गठबन्धन पर हथौड़ा चलाना खेत मजदूरों की जिम्मेदारी बनती है वर्ना आने वाला कल इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा।

यूनियन के नेता ने खेत मजदूरों की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम खेत मजदूर किसी की कृपा पर जिन्दा नहीं है हमने सरकार से लड़कर अपना अधिकार लिया है खेत मजदूरों ने मनरेगा के लिए अपनी शहादत दी है, संघर्ष किया है, करोड़ों लोगों के लिए रोजी–रोटी का एकमात्र साधन है उसको भी देश के प्रधानमंत्री समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। उसको हम लोगों की असफलता का स्मारक बता रहे हैं जबकि इसी मनरेगा ने कोरोना पीरियड में देश के करोड़ों प्रवासी मजदूरों को काम देकर उनके पेट भरने का साधन बना। आज हमारी यूनियन शहरी गरीब मजदूरों के लिए मनरेगा जैसे कानून बनाने की मांग कर रही है यूनियन लगातार इस पर आन्दोलन भी कर रही है। वर्ष भर में 200 दिन का काम, 600 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी, खेत मजदूरों के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च स्तर तक नि:शुल्क शिक्षा, पक्के मकान के लिए पांच लाख रुपये, खेत मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी केन्द्रीय कानून बनाने, खेत मजदूरों, दलितों, आदिवासियों के सामाजिक सुरक्षा की गारण्टी हमारी प्रमुख मांगों में शामिल हैं इस फासीवादी, साम्प्रदायिक सरकार में इन सब मांगों का पूरा होना मुमकिन नहीं है अब सिर्फ निर्मम संघर्ष का रास्ता बचा है। हम सभी मजदूरों को धर्म, सम्प्रदाय, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषा के सवाल से उपर उठकर इस बेशर्म सरकार को जड़मूल से उठाकर अरबियन सी में फेकने की आवश्यकता है तभी खेत मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है।

सम्मेलन के अन्त में एक 11 सदस्यीय कौंसिल का गठन किया गया, जिसके उर्मिला सक्सेना अध्यक्ष, राजकुमार व ममता कश्यप उपाध्यक्ष, राम किशोर रस्तोगी महामंत्री, अमरदीप सिंह व भूरी कश्यप मंत्री और गफ्फार कोषाध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन को भाकपा जिला मंत्री अमरोहा नरेश चन्द्रा व महिला फेडरेशन की जिला मंत्री रितु रस्तोगी ने भी सम्बोधित किया, सम्मेलन में राज्य सम्मेलन के लिए 10 प्रतिनिधियों का चुनाव भी किया गया। संचालन रामकिशोर रस्तोगी ने किया।

खेत मजदूर यूनियन के होने वाले 14वें राज्य सम्मेलन की तैयारियां

सोनभद्र में कैमूर विश्वविद्यालय की मांग के साथ होगा सम्मेलन

रेनूकुट: नगर स्थित हिंडाल्को प्रगतिशील मजदूर सभा के यूनियन कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कौंसिल व उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक सोनभद्र में होने वाले खेत मजदूर यूनियन के चौदहवें राज्य सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता लल्लन राय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जहां उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश महामंत्री फूलचंद्र यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश विषम परिस्थितियों की दौर में चल रहा है। हर जगह नफरत की राजनीति की जा रही है, देश के अंदर अपराध चरम सीमा पर है बहू, बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं सड़कों पर

खुला तांडव मचाया जा रहा है मणिपुर का घटनाक्रम इसका सीधा उदाहरण हैं। जिस शर्मसार करने वाली घटना की हम निंदा करते हैं। पूरे देश में जल, जंगल और जमीन की लड़ाई तेज हो गई है। देश की स्थिति बद से बद्तर होती जा रही है कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सत्तासीन भाजपा सिर्फ नफरत की राजनीति पर सत्ता पर काबिज होने के फिराक में लगी हुई है। ऐसे में हम कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंगठनों के लोगों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन की प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है कि चार राज्यों की सीमाओं को समेटे इस आदिवासी बाहुल्य जनपद सोनभद्र में यूनियन का चौदहवां राज्य सम्मेलन कराया जाएगा। जहां जल, जंगल,जमीन को बचाने के लिए इसके साथ यहां शोषित पीड़ित और वंचितों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जनपद में एक अदद केंद्रीय कैमूर विश्वविद्यालय की स्थापना कराने के लिए ही खेत मजदूर यूनियन का चौदहवां राज्य सम्मेलन कराने का निर्णय किया गया है। बैठक में इस दौरान तीन दिवसीय 1–3 अक्टूबर को होने वाले यूनियन के राज्य सम्मेलन को सुव्यवस्थित संपन्न कराने के लिए लल्लन राय के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कमेटियों का भी गठन किया गया और सबकी जिम्मेदारी तय की गयी। बैठक में प्रमुख रूप से लालता प्रसाद तिवारी, पशुपतिनाथ विश्वकर्मा, प्रदीप कन्नौजिया, बुद्धि राम, अमरनाथ सूर्य, लता सिंह, देव कुमार विश्वकर्मा, मुन्नी लाल दिनकर, दूर्गा प्रसाद, सी. पी. माली, ज्योति रावत, कन्हैया लाल, राजेन्द्र प्रसाद, के के सिंह सहित दर्जनों की संख्या में अन्य उपस्थित रहे। बैठक का संचालन भाकपा जिला सचिव आर के शर्मा ने किया।

31 जुलाई, कथाकार प्रेमचंद की 143वीं जयंती

'प्रेमचंद का साहित्य और किसानों के सवाल'

जाहिद खान

हिन्दी–उर्दू साहित्य में कथाकार प्रेमचंद का शुमार, एक ऐसे रचनाकार के तौर पर होता है, जिन्होंने साहित्य की पूरी धारा ही बदल कर रख दी। प्रेमचंद के सम्पूर्ण साहित्य पर यदि नजर डालें तो, उनका साहित्य उत्तर भारत के गांव और संघर्षशील किसानों का दर्पण है। उनके कथा संसार में गांव इतनी जीवंतता और प्रमाणिकता के साथ उभर कर सामने आया है कि उन्हें ग्राम्य जीवन का चितेरा भी कहा जाता है। प्रेमचंद अकेले किसान की ही कहानी नहीं कहते हैं, बल्कि किसान की नजर से पूरी दुनिया की कहानी भी कहते हैं। बनारस जिले के छोटे से गांव लमही में जन्मे मुंशी प्रेमचंद का सारा जीवन किसानों के बीच बीता। वे किसानों के साथ रहे, उनके हर सुख–दुख में हिस्सेदारी की। जाहिर है कि जिस परिवेश मे उनका जीवनयापन हुआ, उसमें गांव–किसान खुद–ब–खुद उनकी चेतना का अमिट हिस्सा बनते चलते गए। 'वरदान', 'सेवासदन', 'रंगभूमि', 'प्रेमाश्रम' और 'कर्मभूमि' वगैरह उनके कई उपन्यासों की कहानी किसानों, खेतिहर मजदूरों की जिंदगानी और उनके संघर्षो के ही इर्द–गिर्द घूमती है। इन उपन्यासों में वे औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, सामंतशाही, महाजनी सभ्यता और तमाम तरह के परजीवी समुदाय पर जमकर निशाना साधते हैं। भारतीय गांवों का जो सजीव, मार्मिक चित्रण प्रेमचंद ने अपने उपन्यास 'गोदान' मे किया है, हिन्दी साहित्य में वैसी कोई दूसरी मिसाल हमें ढूंढ़े नहीं मिलती।

प्रेमचंद ने अकेले उपन्यास में नहीं, बल्कि कहानियों और अपने लेखों में भी किसानों के सवाल उठाए। वे किसानों की सामाजिक–आर्थिक मुक्ति के पक्षधर थे। 'आहुति', 'कफन', 'पूस की रात', 'सवा सेर गेहूं' और 'सद्गति' आदि उनकी कहानियों में किसान और खेतिहर मजदूर ही उनके नायक हैं। सामंतशाही और ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था किस तरह से किसानों का शोषण करती है, यह इन कहानियों का केन्द्रीय विचार है। साल 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति से एक विचार, एक चेतना मिली जिसका असर सारी दुनिया पर पड़ा। प्रेमचंद भी रूसी क्रांति से बेहद प्रभावित थे। अपने दोस्त के नाम एक खत में उन्होंने इसका साफ जिक्र किया है, ''मैं बोल्शेविकों के मतामत से कमोबेश प्रभावित हूं।'' वर्गविहीन समाज का सपना प्रेमचंद का सपना था। ऐसा समाज जहां वर्ण, वर्ग, लिंग, रंग, नस्ल, भाषा, धर्म और जाति के नाम पर कोई भेद न हो। शुरुआत में महात्मा गांधी के अहिंसक आन्दोलन में अपार श्रद्धा रखने वाले प्रेमचंद का आदर्शवाद उनके आखिरी काल में लिखे हुए साहित्य में टूटता दिखता है। साल 1933 में एक समाचार पत्र के अपने सम्पादकीय में वे लिखते हैं, ''सामाजिक अन्याय पर सत्याग्रह से फतेह की धारणा निःसन्देह झूठी साबित हुई है।'' यही नहीं आगे चलकर अपने उपन्यास के

एक पात्र से जब वे यह वाक्य बुलवाते हैं, ''शिकारी से लड़ने के लिए हथियार का सहारा लेना जरूरी है, शिकारी के चंगुल में आना सज्जनता नहीं कायरता है।'' तब हम यहां उपन्यास 'सेवासदन', 'रंगभूमि', 'कायाकल्प', 'कर्मभूमि' के लेखक से इतर एक दूसरे ही प्रेमचंद को साकार होता देखते हैं। इसके बाद ही प्रेमचंद 'गोदान' जैसा एपिक

उपन्यास, 'कफन' जैसी कालजयी कहानी और दिल को झिंझोड़ देने वाला अपना आलेख 'महाजनी सभ्यता' लिखते हैं। उनकी इन रचनाओं से पाठक पहली बार भारतीय समाज की वास्तविक और कठोर सच्चाईयों से सीधे–सीधे रू–ब–रू होता है।

प्रेमचंद का युग हमारी गुलामी का दौर था। जब हम अंग्रेजों के साथ–साथ स्थानीय जागीरदारों, सामंतों की दोहरी गुलामी भी झेल रहे थे। प्रेमचंद दोनों को ही अवाम का एक समान दुश्मन समझते थे। किताब 'प्रेमचंद घर में' के एक अंश में वे अपनी पत्नी शिवरानी देवी से कहते हैं,''शोषक और शोषितों मे लड़ाई हुई, तो वे शोषित, गरीब किसानों का पक्ष लेंगे।'' प्रेमचंद की कहानी, उपन्यासों में यह पक्षधरता और प्रतिबद्धता हमें साफ दिखलाई देती है। उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में वे जहां सामूहिक खेती और वर्गविहीन समाज की वकालत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर विदेशी शासन और शोषणकारी जमींदारी गठबंधन का असली चेहरा बेनकाब करते हैं। उनकी निगाह में आजादी का मतलब दूसरा ही था, जो शोषणकारी दमनचक्र से सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के बाद ही मुमकिन था। उपन्यास 'प्रेमाश्रम' के माध्यम से प्रेमचंद एक ऐसे कानून की जरूरत बताते हैं, ''जो जमींदारों से असामियों को बेदखल करने का अधिकार ले ले।'' यह भी मानना था, आर्थिक आजादी के बाद ही वास्तविक आजादी मुमकिन है। उपन्यास 'प्रेमाश्रम' में पात्रों के बीच आपसी संवाद है,''रूस देश में काश्तकारों का ही राज है, वह जो चाहते हैं, करते हैं।'' और कादिर कौतुहल से कहता है, ''चलो ठाकुर उसी देश में चलें।'' कहा जा सकता है कि काल और अनुभव की व्यापकता से प्रेमचंद के विचारों में बदलाव आता गया, जो बाद में उनकी कहानी, उपन्यास, लेखों में साफ परिलक्षित होता है।

पिछले साल ही हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है, लेकिन इन सात दशकों के दौरान देश के हालात जरा से भी नहीं बदले हैं। देश में बीसवीं सदी के आखिरी दशक में नव–उदारवादी नीतियों के अमल में आने के बाद, यूं तो पूरा आर्थिक परिदृश्य ही बदल गया। हर क्षेत्र में इन नीतियों का व्यापक असर पड़ा। लेकिन उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों ने सबसे ज्यादा हमारी खेती–किसानी को प्रभावित किया। कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश कम होना शुरू हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसी नीतियां भी अपनायी गई, जिनसे किसानों का जीवन आहिस्ता–आहिस्ता तबाह होने लगा। खेती की जमीन किसानों से छीनकर कारपोरेट को दी जाने लगीं। बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के उत्पादन और विक्रय की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल कर लिया गया। जिसकी वजह से इन सबके दाम असाधारण तौर पर बढ़े। दूसरी ओर, सरकार ने किसानों को सब्सिडी देना कम कर दिया या पूरी तरह से खत्म ही कर दी। जिसका नतीजा यह हुआ कि खेती–किसानी, किसानों के लिए वैसे ही घाटे का सौदा बनी हुई थी, अब उसके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल हो गई। कर्ज में डूबा किसान, फांसी को गले लगाने लगा। आलम यह है कि इन तीन दशकों में चार लाख से ज्यादा किसानों ने पूरे देश में आत्महत्या की है। जिसमें अकेले महाराष्ट्र में पचास हजार से अधिक किसानों ने अपनी जान दी है। किसानों को कर्जे से उबारने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें कई आर्थिक पैकेज और कर्ज माफी जैसी लोकलुभावन योजनाएं लेकर आई, मगर किसानों के हालात नहीं सुधरे। बल्कि और भी ज्यादा बदतर होते चले गए।

किसानों की सबसे बड़ी समस्या, अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलना है। किसानों की बरसों से मांग रही है कि उन्हें उनकी उपज का लागत खर्च से दोगुना मूल्य मिले। साल 2006 में एमएस स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई, उसमें भी उनकी एक अहम सिफारिश थी कि खेती में होने वाले पूरे लागत खर्च का डेढ़ गुना दाम किसान को मिले। फसल चाहे कोई भी हो। लेकिन किसानों की इस मांग का किसी भी सरकार ने निराकरण नहीं किया है। अलबत्ता उनसे हर चुनाव में यह वादा जरूर किया जाता है। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन चला, उसमें किसानों की एक अहम मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करना है। तेरह महीने चले किसानों के इस आंदोलन के आगे केन्द्र की मोदी सरकार ने घुटने टेकते हुए, तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को तो वापिस ले लिया, मगर एमएसपी को कानूनी गारंटी प्रदान करने की दिशा में अभी तलक कोई कदम नहीं बढ़ाया है। किसानों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है। प्रेमचंद ने अपने संपूर्ण साहित्य में न सिर्फ किसानों के अधिकारों की पैरवी की, बल्कि इन्हें हासिल करने के लिए उन्हें संघर्ष का रास्ता भी दिखलाया। किसानों के जो मौजूदा सवाल हैं, उनके बहुत से जवाब प्रेमचंद साहित्य में खोजे जा सकते हैं। बस जरूरत उसके एक बार फिर गंभीरता से पाठ की है।

पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध मार्च

सुबोध दत्ता

कोलकत्ताः पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य में हुई हिंसा के विरोध में वाम मोर्चा ने 13 जुलाई को कोलकाता में एक मार्च आयोजित किया। वाम मोर्चा द्वारा बुलाई गई रैली में वाम मोर्चा से जुड़ी पार्टियों के अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस और आईएसएफ भी शामिल हुई।

नामांकन पत्र दाखिल करने के दिन से लेकर पंचायत चुनाव की मतगणना तक ग्रामीण बंगाल में आतंक और अराजकता की स्थिति बनी रही, जो मतगणना के बाद भी नहीं रुकी। पुलिस–प्रशासन–पार्टी विधायकों–सांसदों की मदद से वोट लूट, दमन, विरोधियों पर हमले और यहां तक कि हत्याएं भी की गई। एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। यह जुलूस एस्प्लेनेड से एंटाली मार्केट तक हुआ। इस सामूहिक जुलूस में ग्रामीण और शहरी बंगाल के सभी क्षेत्रों के लोगों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कृषि श्रमिकों, शिक्षकों, प्रोफेसरों ने भाग लिया। एक ही नारा था–पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में 50 लोगों की जान क्यों गयी, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए।

वाम मोर्चा के चैयरमेन बिमान बोस, भाकपा के वरिष्ठ नेता मंजू कुमार मजूमदार, राज्य सचिवमंडल सदस्य गौतम रॉय, गौतम पांडा, कल्याण बनर्जी, शिशंकर गांगुली, छात्र नेता शुभम बनर्जी, सीपीआई (एम) के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, सूर्यकांत मिश्रा, आरएसपी के मनोज भट्टाचार्य, फारवर्ड ब्लॉक के नरेन चट्टोपाध्याय ने वाम मोर्चा के इस संयुक्त मार्च में हिस्सा लिया। इनके अलावा मिहिर बयान, प्रबीर घोष, नेशनल कांग्रेस के आशुतोष चटर्जी, आईएसएफ के नौशाद सिद्दीकी (एमएलए) ने मार्च में हिस्सा लिया।

वाम मोर्चा के अध्यक्ष बिमान बोस ने एंटाली मार्केट में एक संक्षिप्त बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। भाकपा राज्य सचिवमंडल के सदस्य गौतम रॉय ने जुलूस में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। उनके अलावा मोहम्मद सलीम, कांग्रेस के आशुतोष चटर्जी, नरेन चटर्जी, मनोज भट्टाचार्य, नौशाद सिद्दीकी ने भी बात रखी।

संयुक्त किसान मोर्चे का अगरतला में राज्य स्तरीय सम्मेलन

बिक्रमजीत सेनगुप्ता

अगरतलाः संयुक्त किसान सभा का राज्य स्तरीय सम्मेलन 25 जुलाई को किसान–खेत मजदूर भवन, मेलारमथ के परिसर में आयोजित किया गया।

सम्मेलन सुबह करीब 11 बजे एआईकेएस के राज्य संयोजक रासबिहारी घोष, अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता माणिक पाल, एआईकेएस नेता अघोर देबबर्मा के एक अध्यक्षमंडल की अध्यक्षता में शुरू हुआ।

संयुक्त किसान सम्मेलन के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय किसान सभा (कैनिग लेन) के महासचिव हन्नान मौला थे। एआईकेएस (कैनिंग लेन) के राज्य सचिव पबित्रा कर ने सम्मेलन में प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया और पारित किया गया। उसके बाद किसान सभा नेता हन्नान मौला ने सम्मेलन में पिछले कुछ वर्षो में ऐतिहासिक किसान आंदोलन और एसकेएम की आगामी गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। एआईकेएस की ओर से सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिक्रमजीत सेनगुप्ता ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की कारपोरेट नीति के खिलाफ एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया और आरएसएस भाजपा के खिलाफ सभी वर्गो के लोगों को एकजुट करने और एसकेएम के आगामी आंदोलनों को सफल बनाने की अपील की। सम्मेलन को अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा के नेता रघुनाथ सरकार, अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा के नेता गोपाल दास, किसान महासभा के नेता माणिक पाल, जीएमपी नेता राधाचरण देबबर्मा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में 1 अगस्त को एसकेएम की नई राज्य स्तरीय समिति बनाने, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने, देश बचाने, संविधान बचाने के आह्वान के साथ सितंबर और अक्टूबर में महीने भर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सम्मेलन में समापन भाषण दकिसान सभा के राज्य संयोजक रासबिहारी घोष ने किया।

पानीपत किसान सभा का जिला सम्मेलन संपन्न

पानीपत, 30 जुलाई 2023: निकटवर्ती गांव राजा खेडी में आल इंडिया किसान सभा–1936 का पानीपत जिला सम्मेलन मामचंद सैनी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उदघाटन वरिष्ठ किसान नेता एवं मुख्य अतिथि चौ. सूरत देशवाल ने किया और संचालन राम रतन एडवोकेट ने किया। सम्मेलन में ब्रांचों से चुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सभा के निवर्तमान महासचिव सेवा सिंह मलिक ने गतिविधियों की रिपोर्ट पेश की। दर्जन भर प्रतिनीधियों ने रिपोर्ट पर हुई चर्चा में भाग लिया और सकारात्मक सुझाव दिये। रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई।

भाकपा के राज्य सचिव दरियाव सिंह कश्यप, एटक नेता एवं रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रणबीर शर्मा, वकीलों के राष्ट्रीय संगठन आईएएल के नेता पवन कुमार सैनी एडवोकेट आदि ने सम्मेलन को शुभकामनाएं दी और किसान सभा के आंदोलन को सार्थक समर्थन देने का विश्वास व्यक्त किया।

सम्मेलन मे स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशे लागू कराने, फसलों के लिए एमएसपी पर कानून बनाने, बाढ़ से हुए जान, माल, फसल नुकसान का मुआवजा देने, किसानों को बिना आमदनी की शर्त के 10 हजार मासिक वृद्धावस्था पेंशन देने, सभी किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ करने, गैर बासमती चावल के निर्यात से पाबंदी हटाने, युरिया सहित सभी खादों की समय पर आपूर्ति करने, यमुना नदी में बाढ़ रोकथाम के लिए मिले बजट की जांच कराने तथा बाढ़ नियंत्रण में दोषी अधिकारियों को सजा देने आदि मांगें की गई। सम्मेलन में जिले में आल इंडिया किसान सभा– 1936 के सदस्य बनाने, गांव कमेटियों के गठन करने पर जोर दिया गया। अंत में सर्व सम्मति से 21 सदस्यों की जिला कमेटी और सूरत सिंह देशवाल व माम चंद सैनी को सरंक्षक, सेवा सिंह मलिक को प्रधान, शमशेर सिंह मलिक व पिरथी सिंह सैनी को उप प्रधान तथा राम रतन एडवोकेट को महासचिव चुना गया। पूर्व जिला कमेटी की ओर से सभी अतिथियों एवं नव निर्वाचित प्राधिकारियों को शाल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। माम चंद सैनी ने सम्मेलन को सफल करने में राजा खेडी के किसान कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

‘पौदे’, कृश्न चंदर का एक अदबी शाहकार

प्रोफेसर पुनीत कुमार

सूरज निकलने से बहुत पहले रौशनी का फैलना शुरू हो जाता है। जिसे देखकर, सभी मानने लगते हैं कि अब सुबह होने वाली है। हिंदोस्तान को आजादी 15 अगस्त, 1947 को मिली, लेकिन उसका उजाला मुल्क की आब–ओ–हवा में बहुत पहले से घुलने लगा था। इस ‘बहुत पहले’ की शुरुआत बीसवीं सदी के तीस के दशक से ही मान सकते हैं। रावी नदी के तट पर मुकम्मल आजादी लेने की शपथ, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाना, मौलाना हसरत मोहानी के नेतृत्व में मुकम्मल आजादी के प्रस्ताव का 1930 में पास होना, इसी साल नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च, कराची अधिवेशन, और आगे चलकर ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ इत्यादि वह महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनके कारण यह तय हो गया था कि भारत जल्दी ही विदेशी गुलामी से आजाद होने वाला है। दूसरी ओर हिंदुस्तान का हर संवेदनशील इंसान, इस आजादी का न सिर्फ सपने देखने लगा था, बल्कि अपने स्तर पर इसे पाने की लगातार कोशिशें भी कर रहा था। ऐसे नाजुक दौर में उस तबके ने भी जो समाज का सबसे संवेदनशील और सबसे जहीन समझा जाता था, यानी हमारे अदीब या साहित्यकार खामोश नहीं थे। हिंदुस्तानी की गुलामी से लड़ने के लिए जरूरी साहित्य की ही नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लिए भी जरूरी उस साहित्य की रचना का रास्ता साफ करना, उस समय के अदीब जरूरी समझते थे। जो इंसानी अधिकारों, स्वतंत्रता और समानता को मजबूत करता है और जिसे कोई विदेशी शासक व दमनकारी ताकत कमजोर न कर पाए।

आजादी के पहले के अनेक साहित्यकारों की रचनाओं में यह सब देखा जा सकता है। मगर एक व्यवस्थित और मजबूत कोशिश ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ या ‘प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन’ की बुनियाद डालकर की गई। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हुई। जिसकी अध्यक्षता अजीम अफसाना निगार प्रेमचंद ने की। बहुत कम समय में मुल्क के सभी जाने–माने साहित्यकार, शायर–कवि, चिंतक और प्रबुद्ध वर्ग इस आंदोलन एवं संगठन से जुड़ते चले गये। साल दर साल इसकी बैठकें, अलग–अलग शहरों में होती रहीं। आम इंसान की तकलीफों को उस अदब में लिखा और महसूस किया जाने लगा, जिसकी उस वक्त बेहद जरूरत थी। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर साल 1945 में हैदराबाद में उर्दू के तरक्कीपसंद अदीबों (प्रगतिशील साहित्यकारों) की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। जिसमें उस दौर के नामचीन साहित्यकारों ने न केवल शिरकत की थी, बल्कि भविष्य के हिंदोस्तान और तत्कालीन हिंदोस्तान के जद्दोजहद का बेहतरीन खाका भी इस कॉन्फ्रेंस में पेश किया था। उस दौर के एक बड़े साहित्यकार कृश्न चंदर ने भी उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। ‘पौदे’ उनकी वह किताब है, जिसमें उन्होंने हैदराबाद कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट तफ्सील, बहुत ही जीवंत, रोचक और मनोरंजक, तो कहीं–कहीं बहुत ही गंभीर ढंग से लिखी है।

‘पौदे’ के बारे में सज्जाद जहीर लिखते हैं, ‘‘‘पौदे’ साहित्य और पत्रकारिता की मिली–जुली विधा में जिसका नाम रिपोर्ताज है, एक खास हैसियत रखती है। इसमें कॉन्फ्रेंस के ब्यौरे नहीं, बल्कि इसकी फिजा और माहौल को पेश किया गया है।’’ (पेज–13ऋ) कृश्न चंदर के इस रिपोर्ताज को अदबी शाहकार का दर्जा हासिल है। सबसे पहले इस किताब को ‘मकतबा सुल्तानिया’ मुंबई ने 1947 में उर्दू जबान में प्रकाशित किया था। उसके बाद इस किताब के कई संस्करण निकले, मगर हिंदी में यह पहली बार लेखक–पत्रकार जाहिद खान के जुनून की गवाही के शक्ल में साल 2023 में आ पाई है। हिंदी के पाठकों के लिए, जिन्हें साहित्य और खास तौर पर क्लासिक अदब में दिलचस्पी है, उनके लिए यह किताब एक धरोहर की तरह है। जाहिद खान कहते हैं कि ‘‘उन्हें उर्दू लिपि नहीं आती।’’ उसके बाद भी उन्होंने शायर इशरत ग्वालियरी की मदद से किताब का लिप्यंतरण किया है। यह लेखक की साहित्य और उसके मकसद को पाठकों तक कामयाबी से पहुंचाने का एक जुनून ही कहा जाएगा।

रिपोर्ताज की शुरुआत ट्रेन के सफर की जीवंत तस्वीरें पेश करने से शुरू होती है। बंबई के बोरीबंदर स्टेशन से सज्जाद जहीर, कृश्न चंदर, अली सरदार जाफरी, मुल्कराज आनंद, मदन गोपाल, सिब्ते हसन, कैफी आजमी और साहिर लुधियानवी वगैरह एक साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। कृश्न चंदर अपने कलम के जादू से हमारा तआरुफ करवाते हैं। इस सफर में वे अपने साथियों के हाव–भाव, शक्ल–सूरत आदि ब्यौरों का जिस दिलचस्प और मनोरंजक अंदाज में पेश करते हैं, वह वाकई शानदार है। मसलन ‘‘...सज्जाद जहीर, जो कम्युनिस्ट होने के बावजूद अपने नाम से पहले सय्यद लिखते हैं।’’ (पेज–47) ‘‘अचानक अली सरदार जाफरी सर पर आन खड़े हुए। उनकी बे–क्रीज पतलून, बड़े हुए बाल और घूंसा मार्का चेहरा, बड़े–बड़े जफादरी (तजुर्बेकार) अदीबों पर रेशा (संवाहक तार) तारी कर देता है।’’ (पेज–50) इस तरह के चुटीले, दिलचस्प और कसे हुए जुमले पूरी किताब में बिखरे हुए हैं।

आगे वे कॉन्फ्रेंस की शानदार तफ्सीलात पेश करते हैं, ‘‘हॉल में खामोशी थी। पांच हजार आदमी चुपचाप बैठे हुए एक अदबी मकाला सुन रहे थे। उससे पहले ऐसा न हुआ था। यहां मुशायरा न था। खुत्बाना (धर्मोपदेश) अंदाज, तकल्लुम (बातचीत) न था। कोई गहरी फलसफा–तराजी (दर्शनशास्त्र बघारना) न थी। लेकिन लोग खामोशी से सुन रहे थे। पांच हजार आदमी। कॉलेज के तालिब–ए–‘इल्म (विद्यार्थी), स्कूल की लड़कियां, सरकारी मुलाजिम, दुकानदार, रेलवे के मजदूर, बेकार। हर तबके के लोग शामिल थे। और खामोशी से सुन रहे थे। और जब मकाला–निगार (निबंधकार) ने मोरक्को से लेकर जावा तक के आजादी–पंसदों की तहरीक का जिक्र किया, तो हॉल नारों से गूंज उठा। और जब अदब में इश्तिराकियत का जिक्र आया, इंसानियत का जिक्र आया, एक बेहतरीन निजाम–ए–जिंदगी (जीवन का विधान) का जिक्र आया, इश्क की इंकलाबी माहियत (क्रांतिकारी बदलाव) का जिक्र आया। और उन तबकों का जिक्र आया, जिन पर हमारे अदब के दरवाजे अभी तक बंद हैं, तो साम‘ईन (श्रोतागण) के दिलों के तार झनझना उठे।’’ (पेज–81) वाह ! क्या सुनने वाले और क्या कहने वाले थे और क्या माहौल था ! इस प्रकार के दृश्य आज के संदर्भ में यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद हिंदोस्तानी अवाम की सारी ताकत आजादी पाने को ही अपना हासिल मान चुकी है। आजादी के बाद के सारे जरूरी काम उन्हें नहीं करना है, इसे भी मान चुके हैं। किसी साहित्यिक जलसे में पांच हजार का मजमा, क्या आज इकट्ठा हो सकता है ?

किताब में सभी अदीबों के बीच आपस में हँसी–मजाक तो चलता ही रहता है, इसके साथ ही कृश्न चंदर कई मौकों पर अपने साथियों की बहुत ही सहज तरीके से तारीफ भी कर जाते हैं। ‘‘ये हर महफिल में शायर क्यों छा जाता है? और क्यों अफसाना सुनते ही लोगों को जम्हाइयाँ आने लगती हैं। काश, मेरा हर अफसाना फिराक की रुबाई की तरह खूबसूरत होता।’’ (पेज–98) कृश्न चंदर, मुल्क के गरीब अवाम की तंगहाल जिंदगी का जिक्र और रईसों की ऐश–ओ–आराम की जिंदगी पर तंज करते हैं, तो यह लिखने में भी नहीं हिचकते ‘‘....ये उनका सब्ज (हरी) वर्दी में मलबूस बैरा है। ये फटे हुए कॉलर वाला अली सरदार जाफरी है। ये अखरोट का मेज है। जिस पर कश्मीर के कारीगरों ने हसीन पच्चीकारी की है। वो रिफिअत सरोश का भूरा बिस्तर है। जिसमें दर्जनों पैबंद लगे हैं। ये चांदी की सुराही है। और तांबे का लोटा है। ये कमखाब (बूटी दार रेशमी कपड़ा) की रजाई है। वो खद्दर की ओढ़नी है। ये मौत है। वो जिंदगी है।..ये माजी है. ..वो मुस्तकबिल है। ये अंधेरा है....वो उजाला है।’’ (पेज–106) जिंदगी की तकलीफों से वाकिफ और उससे फिक्रमंद होने के बावजूद, कृश्न चंदर को मुस्तकबिल के सुनहरे अंजाम पर पूरा यकीन था। लिहाजा वे मौत–जिंदगी, अंधेरा–उजाला जैसे अल्फाजों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं।

‘पौदे’ खत्म करते–करते कृश्न चंदर, पाठकों को इस कदर चौंकाते हैं कि वे भावुकता के सैलाब में डूब जाते हैं। यकीन नहीं आता कि खुद की अहम जरूरतों, जो जिंदगी को मौत की सिरहन दे सकती हो, को नजरअंदाज करके कोई शख्स किसी अदबी जलसे को कामयाब बनाने के लिए जी–जान से लगा रह सकता है। ‘पौदे’ का हिंदी में शाब्दिक अर्थ ‘पौधे’ होता है। किताब का नाम ‘पौदे’ रखने के पीछे लेखक का मकसद, शायद ये था कि प्रगतिशील साहित्य का यह पौधा अभी दिनों–दिन और फले–फूलेगा। अभी तो यह शुरुआत है, आगे इस पौधे को एक वृक्ष बनना है। और यह हकीकत भी है। साल 1945 का यह पौधा अब पेड़ बन चुका है। हालांकि इसे सुखाने की तमाम कोशिशें नाकामयाब हुई हैं। ‘पौदे’ बेशक, कृश्न चंदर का एक बेहतरीन रिपोर्ताज है। किताब में कुल बारह अध्याय हैं। जिसका बहुत ही उम्दा लिप्यंतरण जाहिद खान ने किया है। लिप्यंतरण के साथ उन्होंने फारसी, अरबी के कठिन लफ्जों के हिंदी मायने उस लफ्ज के साथ ही कोष्ठक में दिए हुए हैं। जिससे हिंदी पाठकों को उन्हें समझने में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। बावजूद इसके अगर किताब का लिप्यंतरण और भावानुवाद दोनों एक साथ हो जाता, तो इस किताब की भाषा में और भी रवानगी आ जाती। जाहिद खान ने ‘पौदे’ को हिंदी के संवेदनशील पाठकों तक पहुंचाने में जो मेहनत की है, उसके लिए वह वाकई मुबारकबाद के हकदार हैं।

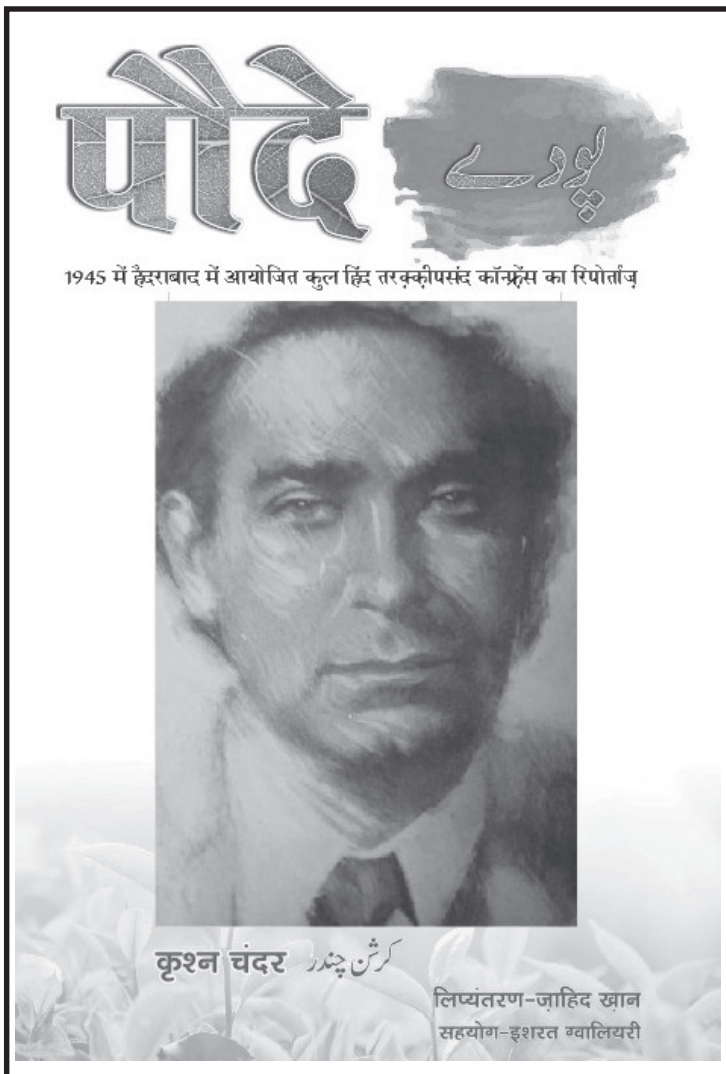

पुस्तक समीक्षा
पौदे (रिपोर्ताज), लेखक: कृश्न चंदर
उर्दू से हिंदी लिप्यंतरण: जाहिद खान
प्रकाशक: एशिया पब्लिशर्स, दिल्ली 110085
पेज रू 116, मूल्य रू. 200

नाकाम डबल इंजन सरकार, मणिपुर...

पेज 5 से जारी...

नहीं किया जाएगा। ऐसे में आज प्रधानमंत्री स्वयं क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफा लेकर मैतईयों को नाराज कर सकते हैं?'' (साभारः दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, 28 जुलाई 2023)।

स्तंभकार चेतन भगत इशारा करते हैं कि मणिपुर की मौजूदा समस्या भाजपा के बहुसंख्यकवाद की वजह से पैदा हुई है और उनके अनुसार, इसकी अति हो रही है। वह लिखते हैंः ''मणिपुर से सामने आए वीडियो ने देश की चेतना को झकझोरा है। यह तथ्य कि वर्ष 2023 में एक भीड़ खुलआम ऐसा कर सकती है, विचलित कर देने वाला है। स्थानीय समुदायों में चाहे जितने मतभेद हों, इस तरह के कृत्यों को कतई न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता.....देशवासियों ने जिस तरह से एक स्वर में इस कृत्य की निंदा की है, उससे भारतीय समाज के बारे में भी कुछ पता चलता है।'' आगे वह लिखते हैंः ''लेकिन जब बहुसंख्यकवाद की अति हो जाती है– जैसा कि मणिपुर में हुआ जिसमें बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों से दुर्व्यवहार किया गया– तो यही लोग उसका विरोध भी करते हैं। इसका यह मतलब है कि भले ही भारतीयों में थोड़ी–बहुत धार्मिक श्रेष्ठता का बोध हो, लेकिन वे हरगिज नहीं चाहते कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी तरह का अमानवीय या हिंसक बर्ताव किया जाए। और यही बात भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि अगर बहुसंख्यकवाद की राजनीति को लेकर देश में यह भावना घर करने लगी कि ''अब कुछ ज्यादा हो रहा है'' और उसके कुछ प्रतिशत वोट भी घट गए तो इसका चुनाव नतीजों पर खासा पड़ सकता है।'' (साभारः दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, 27 जुलाई 2023)।

मणिपुर में, महिलाओं के खिलाफ अपराध भयावह

मणिपुर में जारी हिंसा के संबंध में दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 31 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के वीडियो को भयावह करार दिया। अदालत ने सरकार के रवैये पर कठोर टिप्पणियां की। देश में अजीब हालात पैदा हो गए हैं। 3 मई 2023 से मणिपुर जल रहा है, हिंसा हो रही है, लोग मर रहे हैं, राज्य का सामाजिक तानाबाना ध्वस्त हो गया है, सैंकड़ों लोग मर रहे हैं, अनगिनत जख्मी हो गए हैं, सरकारी और गैर–संपत्तियां जल रही हैं– नष्ट हो रही हैं, कानून एवं व्यवस्था खत्म हो गई है और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों एवं सेना की तैनाती के बावजूद हालात सुधर नहीं रहे हैं। तीन मई जिस दिन मणिपुर में हिसा शुरू हुई, उसके बाद प्रधानंत्री ने पूरी खामोशी अपना ली और 19 जुलाई को जब मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हैवानियत की धटना सोशल मीडिया पर आ गई और भारत क्या पूरी दुनिया में थू–थू होने लगी तब कहीं थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री की खामोशी टूटी और उन्होंने उस घटना पर दुख और संवेदना व्यक्त की, परंतु संसद के बाहर।

जब संसद चल रही थी तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी थी कि मणिपुर की स्थिति पर और वहां हो रही हैवानियत और विनाशलीला पर संसद में आकर देश को जनकारी देते और स्थिति को सुधारने के संबंध में कुछ कदम उठाने के लिए देश को आश्वस्त करते। मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री को संसद में आकर मणिपुर के बारे में बोलने में क्या डर लग रहा है?

20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ। तब से ही विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आएं और मणिपुर के संबंध में बताएं। प्रधानमंत्री संसद में आने और मणिपुर के हालात के बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष मांग कर रहा है कि मणिपुर के संबंध में संसद में नियम 267 के तहत चर्चा की जाए जिसके तहत चर्चा समयबद्ध नहीं बल्कि विस्तारित हो सकती है और चर्चा के बाद मतदान भी हो सकता है। मतदान से पता चलता है कि कौन सी पार्टी किस पक्ष में है। परंतु सरकार चाहती है कि इस पर नियम 176 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा हो। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष यह मांग भी कर रहा है कि मणिपुर पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री दें न कि गृहमंत्री। परंतु सरकार चाहती है कि इस पर अल्पकालिक बहस हो और मतदान भी न हो। इस मामले में संसद में 20 जुलाई के बाद से लगातार गतिरोध जारी है, सरकार मणिपुर पर संसद में बहस से भाग रही है, प्रधानमंत्री संसद में आने और मणिपुर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं।

प्रधानमंत्री को मणिपुर में हो रही हिंसा एवं बिगड़ते हालात पर जवाब देने के लिए मजबूर करने के लिए विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी रख दिया है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बहस के दौरान विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और प्रधानमंत्री को बोलना ही पड़ेगा।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिकाः भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़ः प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाषः 011–23523349, 23529823
ईमेलः pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोनः 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोनः 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोटः आप भेज सकते हैंः
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरणः
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंटः 32074674284, आई.एफ.सी. कोडः SBIN0009371

एक घुमक्कड़ क्रांतिकारी की जीवनगाथा

पेज 9 से जारी...

रिपब्लिक के लोगों को संबोधित करने तक ही सीमित नहीं रहे। 1919 में उन्होने "बोलशेविज्म और इस्लामिक राजनिकाय" शीर्षक से एक पर्चा प्रकाशित किया, जिसमें उन्होने पूरब के कामकाजी मुसलमानों से अपील की कि वे "ब्रदर लेनिन और रूस की सोवियत सरकार का अनुगमन करें।"

ताशकंद में लिखा गया यह पर्चा अरबी, फारसी, तथा हिन्दी में अनूदित किया गया, और आसपास तथा मध्यपूर्व में बांटा गया। यह पर्चा भारत भी पहुंचा, लेकिन ब्रिटिश हकूमत के क्रोध के चलते इसके खिलाफ जब्ती अभियान चलाया गया। लेकिन नयी दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स में ब्रिटिश खुफिया एजेंसी की फायल में इसकी एक प्रति उपलब्ध है। इस पर्चे की विषयवस्तु के गहन अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उपनिवेशवादियों की प्रतिक्रिया इसके विरूद्ध इतनी कठोर क्यों थी।

इस पर्चे में बरकतुल्ला ने लिखा कि "सोवियत रिपब्लिक का कट्टर शत्रु ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, जो कि एशियाई देशों को बाह्य गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने की आशा लगाए हुये है। मानव आजादी को कुचलने के लिये इसने अपनी सेनाओं को तुर्किस्तान की ओर भेजा है। दुनियाँ और एशियाई राष्ट्रों के मुसलमानों के लिये अब समय आ चुका है कि वे रूसी समाजवाद के महान सिद्धांतों को समझें, और सही आजादी की रक्षा के लिये, ब्रिटिशर्स के नापाक हमलों और इरादों को पीछे धकेलने के लिये बोल्शेविक सेनाओं का साथ देना चाहिए। ओ, मुसलमानो! इस आकाशीय संदेश को सुनोरू आजादी, बराबरी और भाईचारे के प्रति उठ खड़े हो, जिसे लेनिन और सोवियत सरकार तुम्हारे लिये पेश कर रही है।"

बरकतुल्ला ने सोवियत रूस में हो रही घटनाओं का गहरा विश्लेषण प्रस्तुत किया, समाजवादी क्रान्ति के तर्कों को समझाते हुये पूरब के लोगों खासकर मुसलमानों की आवश्यकताओं और हितों के प्रति सोवियत सत्ता के वास्तविक रुख का विवरण दिया।

उन्होंने कहा– "सभी मुस्लिम देश ब्रिटिश साम्राज्यवादियों, रूस के अनियंत्रित सम्राट तथा लुटेरे फ्रांसीसी और इटेलियन्स द्वारा लूटे गए और रौन्दे गये".....

"..... मुस्लिम कब्रिस्तानों के दीपक, उन दूसरे निरंकुश मुस्लिम शासकों, जिनका कि धार्मिक विश्वास अपने ही देश को बेचने वाला था, द्वारा बुझा दिये गये। ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा इटेलियन्स ने अपनी हड़प नीति के लिये उत्तर अमेरिका की रिपब्लिकन सरकार को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया, और अमेरिकी सेना की मदद से अपने प्रतिद्वंदियों पर बढ़त बना ली–.. आज एक भी आजाद मुस्लिम राष्ट्र नहीं है।" वे अपने पाठकों के लिये आगे लिखते हैं, अभी भी आशा की किरणें मौजूद हैं, क्योंकि रूसी निरंकुशता के समाप्त होने के बाद, मानवता की मुक्ति के लिये योजना, "आज लेनिन के द्वारा सिद्धांत से व्यवहार में उतारी जा चुकी है, और आज उसे महान नैतिक और भौतिक समर्थन प्राप्त हो रहा है। रूस और तुर्किस्तान की व्यापक सीमाओं का शासन मजदूरों के हाथ में आ गया है. .....जाति, धर्म और वर्ग का भेद मिट गया है..... ओ बंधुओ! समझिए, आपको रूसी राष्ट्र और रूस की वर्तमान सरकार से पीछे नहीं हटना है।"

सत्य की यह आवाज और सोवियत राज्य के साथ मुस्लिम देशों की एकजुटता का यह आह्वान, जो कि अपने क्रियाकलापों से पूरब के उत्पीड़ित लोगों के हितों के प्रति वफादारी निभा चुका था, भारत और अफगानिस्तान, ईरान और टर्की में सुना गया।

लेकिन इस आवाज से ब्रिटिशर्स बहुत घबराये। इस्लाम पर तजुर्बेकार ब्रिटिश विशेषज्ञों के अनुसार, इस्लामिक सिद्धांत बैतुल–उल–माल का बरकतुल्ला का संदर्भ, जो कि एक न्यायपूर्ण समाज के सोशलिस्ट आदर्शों को ही पूरी तरह व्यक्त करता था, ने अधिक खतरा पैदा किया।

इसकी काट के लिये ब्रिटिश इंटेलिजेंस ब्यूरो ने "बोलशेविज्म एंड इस्लाम" नामक अपना पर्चा निकाला, जिसमें समाजवाद के निर्माण के बारे में हर संभव भ्रामक तथ्य दोहराए गये थे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के काशघर में तैनात मुखिया पी. टी. एथेर्टन को खासतौर पर धन्यवाद, जो कि मध्य एशिया में क्रांति के दुश्मनों की हथियारों और धन से मदद किए जाने के लिये कुख्यात रहा है, ने गंदा आक्षेप लगाया कि सोवियत रूस में महिलाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। यह धारणा लगभग सारे पूरब में फैला दी गयी। शेख– उल– इस्लाम ने फतवा जारी कर दिया, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स ने सोवियत मध्य एशिया सहित सारे एशिया में अपने प्रपोगांडा के लिये किया। यह बहुत ही विनाशकारी था, क्योंकि यह पूर्वी सोवियत में सुधारों की क्रांतिकारी प्रक्रिया को नजरंदाज करने वाला था तथा इसने वहाँ वर्ग संघर्ष को बड़ी क्षति पहुंचाई। अशिक्षित आबादी इस्लाम को बोलशेविज्म से "खतरे" की अफवाहों के बारे बहुत संवेदनशील थी। इस तरह मुस्लिम अवाम के साथ एक बड़ी धोखाधड़ी की शुरुआत हुयी, और इसे परवान चढ़ाने को ब्रिटिशर्स ने तब रेडियो, प्रेस और यहाँ तक कि फिल्मों तक का इस्तेमाल किया।

शताब्दी से अधिक बीत चुका है इस दौर को गुजरे। लेकिन आज भी मुसलमानों के समक्ष एक उत्तरी शत्रु की छवि पेश की जाती है, इससे कथित तौर पर इस्लाम को हानि पहुँचती है।

वे 1922 तक रूस में रहे और तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। निश्चय ही, मोहम्मद बरकतुल्ला ने सोवियत यूनियन और भारत के बीच संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने लेनिन के लिये अमानुल्लाह के दूत रूप में सोवियत–अफगान संबंधों को बढ़ाने में निभाई। बरकतुल्ला के प्रयास व्यर्थ नहीं गये और सोवियत क्रांति से प्रभावित हो कर भारत सहित तमाम देशों के संवेदनशील युवा तथा प्रबुद्ध नागरिक आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। उनमें से अनेक ने मजदूर आंदोलन और कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा करने में विशिष्ट भूमिका निभाई।

यहां मौलाना के आखिरी भाषण के शब्दों को याद किया जाना चाहिये जिसमें उन्होंने कहा था: "जो कुछ भी संभव था मैंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया लेकिन यह निराशाजंक है कि देश मेरे जीवनकाल में आजाद नहीं हो सका। हालांकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि युवाओं में जो उत्साह और जागरूपता पैदा हुयी है, वह उन्हें शांति से नहीं बैठने देगी और देश को जल्दी ही विदेशी गुलामी से आजादी मिलेगी।"

प्रोफेसर बरकतुल्ला रूस से जर्मनी चले गये। फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स में अंग्रेजों के खिलाफ अधिवेशन हुआ था जिसमें पंडित जवाहर लाल नेहरू और प्रोफेसर बरकतुल्ला दोनों ही मौजूद थे। इस बारे में पंडित नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि इस अधिवेशन में भारत की पहली निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री और आजाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली और आखिरी मुलाकात थी।

अपनी अगली योजनाओं को अंजाम देने को वे 1927 में बीमारी की हालत में भी राजा महेन्द्र प्रताप के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गये थे, कुछ ही दिनों बाद 20 सितंबर 1927 को अमेरिका में ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उनकी मृत्यु की खबर बिजली की तरह पूरे अमेरिका में फैल गयी और प्रेस एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के माध्यम से यूरोप और एशिया में फैल गई। गमजदा हिंदुस्तानियों और उनके विदेशी मित्रों ने अपने कारोबार बंद रखे।

पाँच दिन तक उनके पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया ताकि उनके चाहने वाले दीदार कर सकें। उसके बाद उनके शरीर को सेक्रेमेंटों से मार्यविले पहुंचाया गया जहां मुस्लिम कब्रिस्तान में यह कर दफनाया गया कि हिंदुस्तान के आजाद होने पर तुम्हारी खाक को हिंदुस्तान पहुंचा दिया जायेगा। अंतिम संस्कार के वक्त भी उनके संघर्षों के साथी राजा महेन्द्र प्रताप भी मौजूद थे। इस तरह एक अजीम इंकलाबी अमेरिकी सरजमीन पर सुपुर्द–ए–खाक कर दिये गये।

भारत की आजादी के लिए जीवन भर एक से दूसरे देश दौड़ने वाले मौलाना बरकतुल्ला की बहादुरी के अनेक किस्से हैं। उनके बारे में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ सेंट्रल यूरोप के सदर के आखिरी शब्द कुछ इस तरह थे–"ये सच है कि एक अजीम इंकलाबी मौलाना बरकतुल्ला भोपाली की मौत हो चुकी है, लेकिन ये भी सच है कि इंकलाब जिंदा है, और हमेशा जिन्दा ही रहेगा।"

यह एक विडम्बना ही है भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन का यह महान योद्धा भारतीय इतिहास के हाशिये पर सिमट गया है। उनके नाम का उल्लेख देश की पाठ्यपुस्तकों में नहीं है और नहीं भारत की संसद के केंद्रीय हाल में उनका चित्र लगाया गया है। हालांकि उनके मूल स्थान भोपाल में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय है।

चुनावी तैयारियों के लिए उदयपुर जिला भाकपा की मीटिंग

उदयपुर, 2 जुलाई 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उदयपुर जिला परिषद की विस्तारित बैठक पार्टी कार्यालय रेती स्टैंड पर सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पंडित जीवराज शर्मा ने की और इसमें राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य, पूर्व राज्य सचिव तारा सिंह सिद्धू एवं राज्य परिषद सदस्य कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे।

बैठक में राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य ने बताया कि उदयपुर जिला राज्य में सबसे अधिक सदस्यों वाला जिला है अतः इसमे पार्टी और पार्टी के जनसंगठनों के कार्यों में विस्तार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस आदिवासी बाहुल्य इलाके में पूर्व विधायक कामरेड मेघराज तावड ने आदिवासी उत्थान के लिए बहुत कार्य किया है और यहाँ के निवासी उनके कार्यों को अच्छी तरह से जानतें हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पार्टी सदस्यता बढ़ाने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। उन्होंने पार्टी शिक्षा और पार्टी साहित्य पर भी जोर देने का निर्देश दिया है इससे पार्टी सदस्यों को पार्टी के सिद्धांतों से लैस किया जा सके और वे पूंजीवादी विचारों से गुमराह न हो सकें।

पूर्व राज्य सचिव कामरेड तारा सिंह सिद्धू ने कहा कि इस क्षेत्र से वो चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और पार्टी विस्तार के लिए वे पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विशेष फंड इकठ्ठा करने पर भी जोर देने की बात कही। जिला सचिव सुभाष श्रीमाली ने पिछली बैठक से अब तक जिला पार्टी के कार्यों के बारे में बताया और पार्टी की कमजोर आर्थिक स्थिति को भी बैठक में रखा। उन्होंने जिले में पार्टी के जनसंगठनों की स्थिति के बारे में भी बताया। जिला सहायक सचिव एवं राज्य परिषद सदस्य हिम्मत चांगवाल ने जिला पार्टी का लेखा जोखा अगली बैठक में रखने पर जोर दिया। उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए संभावित लड़ने वाली सीटों में वहाँ की जन समस्याओं को उठाने और वर्तमान विधायकों की कमियों को प्रचारित करने का सुझाव दिया तथा यह भी कहा कि पार्टी को आने वाले विधानसभा के चुनावों में पिछली विधानसभा चुनावों की तरह इस बार भी उन्हीं विधान सभा क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार खड़े करने चाहिए, जिनसे पार्टी पिछली बार लड़ी थी।

बैठक में जिला सहसचिव गेबि लाल डामोर, सुरेश मीणा, रता राम (देवला), पदम सिंह (सायरा), कमजी राम (झाड़ोल) आदि ने भी अपने विचार रखे। बैठक में यह फैसला लिया गया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगी, जिनसे वो पहले से ही लड़ती आ रही है। बैठक में राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य के प्रस्ताव पर यह भी फैसला लिया गया कि पार्टी की राज्य परिषद की अगली बैठक उदयपुर में जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के प्रथम सप्ताह में रखी जाएगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष पंडित जीव राज शर्मा ने सभी उपस्थित सदस्यों को बैठक में आने के लिए धन्यवाद दिया और बैठक के फैसलों को लागू करने के निर्देश दिये।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 6 – 12 अगस्त, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 4.8.2023

21 विपक्षीय सांसदो ंका दो दिवसीय मणिपुर दौरा

कानून और व्यवस्था की पूर्ण विफलता टीम 'इंडिया' का अवलोकन

हमारे विशेष संवाददाता

विपक्षीय दलों के 21 सांसदों ने 29 और 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा किया और पाया कि सरकारी तंत्र जारी हिंसा को रोकने और मणिपुर की जनता की जीवन रक्षा में पूरी तरह असफल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) टीम अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिली और उन्हें अपने दौरे क दौरान अवलोकनों से निकले निष्कर्षों के आधार पर कहा कि राज्य तंत्र नि:संदेह लगभग तीन महीनों से चली आ रही हिंसा को नियंत्रित करने में असफल रही है। यह सशस्त्र संघर्ष 3 मई को शुरू हुआ था।

16 राजनीतिक पार्टियों के इन सांसदों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने जमीनी परिस्थिति पर लिखा, शांति प्रयासों के लिए सुझाव दिए और इस मुद्दे पर ''प्रधानमंत्री की खामोशी'' पर अफसोस जताया। इस 21 सदस्यीय प्रतिनिधि दल में शामिल हैं–भातरीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदोष कुमार पी, कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा में डिप्टी स्पीकर गौरव गोगोई, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, डीएमके की कनीमोढी करुणानिधि, एनसीपी के पीपी मोहम्मद फैजल, आरएलडी के चौधरी जयंत सिंह, आरजेडी के मनोज कुमार झा, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, वीसीके के तिरुमावलावन, जेडी (यू) के राजीव रंजन (लालन) सिंह और उनकी पार्टी के साथी अनिल प्रसाद हेगड़े, भाकपा (मार्क्सवादी) के ए ए रहीम, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर, आप पार्टी के सुशील गुप्ता, वीसीके के डी रविकुमार, शिवसेना–यूबीटी के अरविंद सावंत, और कांग्रेस के फुलो देवी नेताम और के सुरेश।

सांसदों ने राज्यपाल को बताया कि अभूतपूर्व हिंसा से प्रभावितों की चिंताओं, अनिश्चितताओं, दर्द और दु:खों की कहानियां सुनकर वे स्तब्ध हैं। संसदीय दल ने चन्द्रचुडापुर, मोइरंग और इंफाल के राहत शिविरों का दौरा किया। मेइती और कुकी दोनों ही समुदाय जब से हिंसा शुरू हुई तब से एक दूसरे के प्रति गुस्सा और अलगाव बनाए हुए हैं। इस टीम ने जारी हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

सांसदों की 'इंडिया' टीम ने मणिपुर में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में असफलता के लिए केन्द्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले तीन महीनों से 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। सांसदों ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि राज्य में पिछले 89 दिनों से कानून और व्यवस्था की विफलता के बारे में केन्द्र सरकार को बताए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुप्पी राज्य में हिंसा पर उनकी निर्लज्ज उदासीनता को दिखाती है।

सांसदों ने राहत शिवरों की ''दयनीय'' अवस्था और शिविरों में बच्चों की स्थिति पर राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट किया। छात्रों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है चूंकि सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं और सांसदों ने राज्य और केन्द्र सरकारों से इस मुद्दे का प्राथमिकता के आधार पर निदान करने का अनुरोध किया।

सांसदों की 'इंडिया'' टीम ने राज्यपाल को स्पष्ट किया कि ''पिछले कुछ दिनों से आगजनी और लूटपाट की लगातार खबरों से बेशक यह स्थापित हुआ है कि राज्य तंत्र पिछले तीन महीनों से स्थिति को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असफल रहा है।'' टीम लोगों के पुर्नवास और पुन:स्थापित करने के लिए अविलंब कार्यवाही चाहती है ताकि राज्य में जल्द से जल्द शांति और सद्भाव बहाल हो सके।

टीम ने यह भी कहा कि पिछले तीन महीने से राज्य में इंटरनेट प्रतिबंध से मनगढंत अफवाहें चल रही हैं जिससे पहले से मौजूद अविश्वास बढ़ रहा है।

राज्यपाल ने सांसदों का स्वागत किया और उनसे कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर प्रयास कर रही हैं।

मणिपुर में लावारिस लाशों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन का गृहमंत्री को पत्र

मणिपुर में हिंसा का दौरदौरा जारी है और हालात इतने खराब हैं कि शवगृहों में लाशें अज्ञात एवं लावारिस के तौर पर पड़ी हैं जिसका कारण यही नजर आता है कि उनके परिवार के लोग डरे–सहमे किसी शरणार्थी शिविर में पड़ होंगे और अपने परिवार से जुदा हुए लोगों की तलाश की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे। इम्फाल के शवगृहों में इस तरह लावारिस एवं अज्ञात पड़े शवों के संबंध भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की महासचिव एनी राजा और सचिव निशा सिद्धू ने केंद्रीय गृहमंत्री को निम्न पत्र भेजा है:

मणिपुर में 3 मई 2023 को शुरू हुई हिंसा का नतीजा अकल्पनीय तबाही के रूप में निकला है। हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं, सैंकड़ों मर गए हैं। इम्फाल के जिन अस्पतालों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है, वहां कई शवगृहों में अनेक लावारिस लाशें पड़ी हुई हैं। लगातार जारी हिंसा ने मणिपुर को बुरी तरह त्रस्त कर दिया है और राज्य के लोगों को बेतहाशा मुसीबतों का शिकार होना पड़ा है। परिवार बिछुड़ गए हैं। घर ध्वस्त हो गए हैं। लोगों के मारे जाने से राज्य में सामूहिक चेतना पर ऐसी चोट पहुंची है कि जिसको भूलना भी उनके लिए मुश्किल होगा। अस्पतालों में कोल्ड स्टोरेज के अभाव के कारण पीड़ित परिवारों की परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। वे अपने मृतक परिवार सदस्यों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं।

इस तरह की चिंताजनक स्थिति के प्रकाश में हम निम्न आवश्यक मामलों के समाधान के लिए आपके तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं:

* इससे पहले कि सभी सबूत खत्म हो जाएं, शवगृहों में पड़ी लावारिस लाशों समेत सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करने के लिए किसी प्रतिष्ठित मेडिकल इन्स्टीच्यूट के स्वंत्रत फोरेंसिक विशेषज्ञों के नेतृत्व में तत्काल मेडिकल बोर्ड बनाए जाएं।

* पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर के अस्पतालों को आवश्यक संसाधन–आवंटन किया जाए। यह आवश्यक है कि लोग अपने परिवार के मृतक सदस्यों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर सकें, इसके लिए उचित कब्रिस्तान/ श्मशान स्थान प्रदान किए जाएं।

* जिन परिवारों के लोग गायब हैं या उनके मारे जाने की आशंका है, वे इम्फाल में शवगृहों तक नहीं जा पा रहे हैं। उचित होगा कि सरकार एक अधिकारी को इसके लिए नियुक्त करे, जिनसे संपर्क किया जा सके और जो व्यवस्था करे कि परिवारों को सुरक्षा प्रदान कर उनका शवगृहों तक जाना संभव हो सके ताकि वे अपने मृतक सदस्यों की पहचान कर सकें और जो मृतक सदस्यों की लाशों को परिवारों के हवाले करे।

* मृतक के परिवारों को मणिपुर इम्फाल सुरक्षापूर्वक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए ताकि वे अपने प्रिय मृतक परिजनों की लाशों को लेने का दावा कर सकें और उनका अंतिम संस्कार कर सकें। यह अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें अपने मृतक परिजनों को अंतिम विदाई देने का मौका दिया जाए, ताकि उन्हें कुछ तसल्ली हो।

हम मणिपुर में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए आप द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की अपील करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आगे हिंसा को रोकने के लिए और राज्य में रहने वाली जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं। झगड़े की असली जड़ के कारणों के समाधान और शांति एवं सामान्य स्थिति के लिए टिकाऊ समाधान को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षकारों से संवाद समेत सहयोगात्मक कोशिशें की जानी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.